घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 23, अंक - 22- मंगलवार 24- नवम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

भारत नेपाल को देगा 24 हजार करोड़ की सहायता

8 समझौतों के साथ सरयू-कमला एक्सप्रेस की शुरुआत

नेपाल के बिना हमारे धाम और राम अधूरे : पीएम मोदी



नई दिल्ली,23 नवम्बर 2026। भारत बाढ़ से प्रभावित नेपाल को दीर्घकालिक विकास के लिए 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये की विकास सहायता पैकेज देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बीच गुरुवार को वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने सरयू-कमला एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन अयोध्या से जनकपुर (नेपाल) जाएगी। दोनों देशों ने साझा भविष्य को नई दिशा देने के लिए एक संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह 'विकसित भारत और समुन्नत नेपाल' के अपने-अपने संकल्पों को पूरा करने का ब्लू-प्रिंट है। इसके अलावा बनबासा में नए आईसीपी (इंट्राक्लोजर कंट्रोल) और भैरहवा, सुनाउली और दोधारा चांदनी में आईसीपी के निर्माण में प्रगति की आधारशिला रखी गई। धारचूला (भारत) और दार्चुला (नेपाल) के बीच नए सीमा पार मोटर योग्य पुल का उद्घाटन किया गया। लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना (669 मेगावाट) की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन के द्वितीय चरण का लोकार्पण किया गया। प्रस्तावित सिलीगुड़ी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन के झापा स्थित पेट्रोलियम टर्मिनल की आधारशिला रखी गई। दोनों देशों के बीच 8 समझौता पर भी सहमति बनी है। यह समझौते अपराध जांच,पुलिस प्रशिक्षण,नौकरशाहों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम,आयुर्वेद और परंपरागत औषधि के क्षेत्र में सहयोग, दक्षिण एशिया उपग्रह के उपयोग हेतु उपग्रह संचार (सैटकॉम) नेटवर्क की स्थापना,सतत शहरी विकास से जुड़े तकनीकी सहयोग,स्वास्थ्य एवं दवा क्षेत्र में सहयोग और पशुधन और मत्स्य पालन विकास के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े हैं। बालेन शाह के भारत के पहले द्विपक्षीय दौरे को दोनों देशों की गहरी दोस्ती का प्रतीक बताते हुए मोदी ने साझा इतिहास,संस्कृति और आस्था का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम और माता सीता भारत-नेपाल की साझा सभ्यता के प्रतीक हैं। 2018 में जनकपुर यात्रा को याद करते हुए मोदी ने कहा कि नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे हैं और नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। वहीं,नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने की बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के रिश्ते हिमालय की तरह मजबूत और समुद्र की तरह विशाल हैं। दोनों देशों के लोग एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।

नेपाल के बिना हमारा धाम भी अधूरा है...

मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सिर्फ पड़ोसी देशों का रिश्ता नहीं है, बल्कि दोनों का इतिहास, संस्कृति और परंपराएं भी एक-दूसरे से जुड़ी हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं। उन्होंने 2018 में अपनी जनकपुर यात्रा को याद करते हुए कहा कि भारत और नेपाल का संबंध भगवान राम और माता सीता से भी जुड़ा है। जनकपुर को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है, जबकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है। दोनों जगहों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी रिश्ते का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, 'नेपाल के बिना हमारा धाम भी अधूरा है।' उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंधों की यही खासियत दोनों देशों को करीब लाती है।

भारत-नेपाल के बीच सड़क और सीमा संपर्क मजबूत होगा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सड़क और सीमा संपर्क को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच धारचूला में सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है। साथ ही बनबसा में एकीकृत जांच चौकी की आधारशिला रखी गई है। मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तराखंड और नेपाल के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही आसान होगी। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों को नेपाल से जोड़ने वाली सड़क, रेल और सीमा संपर्क परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

नेपाल को कांडला-पारादीप बंदरगाहों तक पहुंच मिली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नेपाल को गुजरात के कांडला और ओडिशा के पारादीप बंदरगाहों तक पहुंच देगा। इससे नेपाल का दूसरे देशों के साथ व्यापार आसान होगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ बेहतर व्यापार और निवेश से नेपाल की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी।

पीएम मोदी-बालेन शाह ने सरयू कमला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई

प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने हरी झंडी दिखाकर सरयू कमला एक्सप्रेस को रवाना किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच सड़क,रेल और बिजली से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए नींव रखी।

मोदी ने बालेन शाह को दिखाई पीएम गति शक्ति योजना की झलक

प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह को पीएम गति शक्ति योजना की जानकारी दी। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को की थी। इसका मकसद देश में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को बेहतर तालमेल के साथ पूरा करना है। नेपाल में भी कई बार एक बुनियादी ढांचा परियोजना का असर दूसरी परियोजना पर पड़ता है। नेपाल ने पहले भी भारत से इस योजना के बारे में जानकारी साझा करने की इच्छा जताई थी।



भारत एशिया में तीसरा सबसे ताकतवर देश

2026 में पावर स्कोर बढ़कर 40.5 अंक हुआ,ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक की रिपोर्ट

नई दिल्ली,23 नवम्बर 2026। भारत एशिया में सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है। उसने हाल ही में अपनी स्थिति और मजबूत की है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2026 में भारत का कुल पावर स्कोर बढ़कर 40.5 अंक हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में भारत का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा है। इसमें कूटनीतिक स्थिति, रक्षा सहयोग, सांस्कृतिक पहुंच और भविष्य के संसाधनों में सुधार का योगदान रहा। लिस्ट में अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर है। भारत की आर्थिक क्षमता का स्कोर घटकर 26.4 अंक हुआ, फिर भी वह इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा।

कूटनीतिक प्रभाव सबसे मजबूत : कूटनीतिक प्रभाव भारत का सबसे मजबूत क्षेत्र बना रहा। इस श्रेणी में भारत को 70.3 अंक मिले। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्रीय नेतृत्व के आकलन में बड़ा सुधार हुआ। वह तीन स्थान ऊपर पहुंचे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरे सबसे प्रभावी क्षेत्रीय नेता बने। भारत ने अपने आर्थिक रिश्तों में भी सुधार किया। वह इस श्रेणी में दो स्थान ऊपर उठकर सातवें स्थान पर पहुंचा। क्षेत्रीय व्यापार और निवेश संबंधों में अपेक्षाकृत स्थिरता से भारत को फायदा हुआ। इससे उसने कई अन्य देशों से बेहतर प्रदर्शन किया।



रिपोर्ट में आर्थिक क्षमता में गिरावट का दावा

लोवी इंस्टीट्यूट ने भारत की आर्थिक क्षमता में गिरावट की वजह कमजोर रुपए और अर्थव्यवस्थाओं को मापने की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बदली पद्धति को बताया। भारत के विदेशों में निवेश में करीब 20 अरब डॉलर की कमी का भी उसके प्रदर्शन पर असर पड़ा। इसके बावजूद,भारत के भविष्य के संसाधनों का स्कोर बढ़कर 56.2 अंक हो गया। यह सुधार बेहतर आर्थिक अनुमान और देश के सामने मौजूद अवसरों को दिखाता है। रिपोर्ट ने कहा गया कि 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति के नतीजे मिले-जुले रहे, लेकिन एशिया में उसका प्रभाव बढ़ा।

बिहार विधान परिषद के आठ नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ

कार्यकारी सभापति प्रो.रामवचन राय ने दिलाई शपथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल

पटना,23 नवम्बर 2026। बिहार विधान परिषद के आठ नवनिर्वाचित सदस्यों ने सोमवार को शपथ ली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। विधान परिषद के उप भवन सभागार में आयोजित समारोह में कार्यकारी सभापति प्रो. रामवचन राय ने सभी आठ नवनिर्वाचित विधान पार्षदों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सदस्यों में डॉ. संजीव कुमार,सुरेश प्रसाद राय, नरेंद्र प्रसाद सिंह, डॉ. राहुल राज, नीरज कुमार,अनिल कुमार झा, बंशीधर बृजवासी और डॉ. एनके यादव शामिल हैं। शपथ ग्रहण के



बाद सभी नवनिर्वाचित विधान पार्षदों ने मुख्यमंत्री के साथ सामूहिक तस्वीर खिंचवाई। समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार,कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल तथा भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह उपस्थित रहे।

पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंग होगा

9 दिसंबर को विधानसभा में प्रस्ताव आएगा

नई दिल्ली,23 नवम्बर 2026। पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर 'पश्चिम बंगा' किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को इसका ऐलान किया। 9 दिसंबर को विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। देश में अब तक 6 राज्यों के नाम बदल चुके हैं। आखिरी बार 2026 में केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया था।



भाजपा बोली...बांग्ला नाम बांग्लादेश से मिलता-जुलता

पश्चिम बंगाल का नाम 'पश्चिम बंगा' करने के पीछे बीजेपी का मुख्य तर्क राज्य की ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखना है। 1947 में बंगाल के बंटवारे के बाद इसका पश्चिमी हिस्सा भारत में रहा और पश्चिम बंगाल राज्य बना। बीजेपी का कहना है कि 'पश्चिम बंगा' नाम इस इतिहास और राज्य के गठन से जुड़ी पहचान को दर्शाता है।

व्हाट्सऐप वेब के इस्तेमाल में बरतें सावधानी

हर सत्र के बाद लॉगआउट करने की सलाह

नई दिल्ली,23 नवम्बर 2026। केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने व्हाट्सऐप वेब के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर परामर्श जारी करते हुए उपयोगकर्ताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि व्हाट्सऐप वेब का सक्रिय सत्र कुछ परिस्थितियों में उपयोगकर्ता के खाते तक अनधिकृत पहुंच का माध्यम बन सकता है। इसके जरिए साइबर अपराधी संदेश पढ़ने,उपयोगकर्ता की पहचान से दूसरों को संदेश भेजने और संपर्कों तथा समूहों की बातचीत तक पहुंच बनाने में सक्षम हो सकते हैं।नक्शे देखें राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई (एनसीटीएयू) के परामर्श के अनुसार व्हाट्सऐप वेब के दुरुपयोग से धोखाधड़ी, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग जैसी साइबर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में विशेष रूप से कार्यालयों, साझा प्रणालियों,सार्वजनिक कंप्यूटरों और दूसरे व्यक्तियों की पहुंच वाले उपकरणों पर इसका इस्तेमाल करते समय सतर्क रहने की जरूरत है। परामर्श में सरकारी,संगठनात्मक, वित्तीय, गोपनीय और अन्य संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कंप्यूटर पर व्हाट्सऐप वेब का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। साथ ही, जरूरत नहीं होने पर व्हाट्सऐप वेब को लगातार लॉगइन रखने से बचने को कहा गया है। आई4सी ने उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक सत्र पूरा होने के बाद व्हाट्सऐप वेब से अनिवार्य रूप से लॉगआउट करने की सलाह दी है।

गोधरा अग्निकांड के दोषी की सजा निलंबित...मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत,17 साल से जेल में,31 में 11 को अबतक जमानत

नई दिल्ली,23 नवम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषी इरफान सिराज पाड़ा की सजा निलंबित कर दी। कोर्ट ने उसे मेडिकल आधार पर जमानत दी है। गुजरात सरकार ने उसकी मेडिकल स्थिति पर आपत्ति नहीं जताई। इरफान को 2025 में भी समय से पहले रिहाई की मांग पर राज्य सरकार से विचार कराने के लिए अंतरिम पैरोल मिली थी। इस मामले में कुल 31 लोग दोषी ठहराए गए थे। इनमें से अब तक 11 को जमानत मिल चुकी है।

2002 में साबरमती एक्सप्रेस के कोच में लगी थी आग : 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगने से 58 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे कारसेवक सवार थे। इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें 11 को फांसी और बाकी 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।



63 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। बाकी 20 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। दोषियों की अपील 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

2022 से अब तक 10 दोषियों को जमानत मिली

13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अब्दुल रहमान धंतिया उर्फ कंकड्डो उर्फ जंबूरो को छह महीने की अंतरिम जमानत दी थी। उसकी पत्नी को अंतिम चरण का कैंसर था और उसकी बेटियां मानसिक रूप से दिव्यांग थीं। 11 नवंबर 2022 को कोर्ट ने उसकी जमानत 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी थी। दिसंबर 2022 में एक अन्य दोषी फारूक को जमानत दी गई। कोर्ट ने उसके मामले में इस बात पर विचार किया था कि वह 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है।

संपादकीय

नव वामपंथियों के निशाने पर लोकतंत्र

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गत दिनों अमेरिका में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था,चुनाव प्रणाली और अर्थव्यवस्था आदि पर जो टिप्पणियां कीं,वे उनकी भावी राजनीतिक दिशा का संकेत देती हैं। हाल में हैदराबाद में भारत समिट-2026 आयोजित कर उन्होंने इसे वैश्विक अभियान का रूप देने का प्रयास किया। समिट की थीम थी-एक नए विश्व का निर्माण। कांग्रेस ने इसे वैश्विक न्याय,लोकतंत्र,बहुपक्षवाद, मतदाताओं के अधिकार और नफरत की राजनीति के खिलाफ वैकल्पिक विचारों का मंच बताया। इससे उसका वास्तविक उद्देश्य समझना कठिन नहीं है।

इसी समिट के मंच से इटली की पार्टी आफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने जिस अंदाज मेंवोट चोर,गद्दी छोड़ का नारा दिया,वह राहुल गांधी की शैली जैसा ही था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए वे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। आखिर इस समर्थन का मतलब क्या है? यह किसी विदेशी का विपक्ष के माध्यम से भारत के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। राहुल गांधी ने सामने बैठे हुए जिस तरह मुस्कुराकर ताली बजाई,उससे लगता है कि वे अब इसी रास्ते पर चलने वाले हैं।

आज पूरी दुनिया में एक अजीब किस्म के नव वामपंथी उभरे हैं। ये खुद को उदारवादी और वैकल्पिक विचारों का प्रतिनिधि बताते हैं। कुछ देशों की सरकारों में भी इनकी मौजूदगी है। यूरोप से लेकर अमेरिका,अफ्रीका और एशिया तक कट्टर इस्लामवादी भी इनके साथ दिखाई दे रहे हैं और अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की शुरुआत 2017 से कराई गई। इन लोगों से उनका संपर्क और संबंध बना और तब से उनकी भाषा और व्यवहार में बदलाव साफ दिखाई देता है। वे विदेश में भारत विरोधियों से मिलने में न हिचकते हैं और न ही लोकतंत्र,अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,धार्मिक स्वतंत्रता,मानवाधिकार आदि के नाम पर अपने देश की निंदा करने से। यह एक ऐसी चुनौती है,जिससे निपटने के रास्ते तलाशने होंगे। इन नव वामपंथियों के निशाने पर केवल अपने देश के राष्ट्रवादी ही नहीं,बल्कि वे नेता और देश भी हैं,जो अपनी सभ्यता,संस्कृति और क्षमता के बल पर श्रेष्ठ स्थान बनाने का माद्दा रखते हैं और अपने लोगों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। लगता है कि कांग्रेस में इसी श्रेणी के रणनीतिकारों ने राहुल गांधी को भारत में ऐसा सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया,ताकि यह स्थापित किया जा सके कि देश के साथ-साथ विदेश में भी उनके संपर्क,सम्मान और अभियान को व्यापक समर्थन प्राप्त है।

गुरु नानक जयंती : समाज को समरसता,समानता- मानवता का संदेश

विश्व की महान संत परंपरा में गुरु नानक देव जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका जीवन,विचार और आध्यात्मिक दर्शन केवल सिख धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं,बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। 24 नवंबर 2026 को मनाई जाने वाली गुरु नानक जयंती हमें एक बार फिर उनके उन महान विचारों को आत्म सात करने का अवसर देती है,



सौरभ वार्ष्णेय
उत्तमनगर,नई दिल्ली

प्रतीकात्मक: दैनिक घटती-घटना

जिनमें सामाजिक समरसता,आपसी भाईचारे,समानता,प्रेम,सेवा और मानवता का संदेश समाहित है। गुरु नानक देव जी ने ऐसे समय में समाज को नई दिशा दिखाई,जब जाति पाति,ऊंच-नीच,धार्मिक भेदभाव,अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां मानव समाज को बांट रही थीं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि ईश्वर एक है और उसकी बनाई हुई समस्त मानव जाति समान है। गुरु नानक देव जी का दर्शन किसी एक वर्ग,जाति या समुदाय तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म,जाति,धर्म,धन अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं,बल्कि उसके कर्मों और आचरण से होनी चाहिए। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव और आडंबरों का विरोध करते हुए मानवता को सर्वोपरि रखा। उनका प्रसिद्ध संदेश एक ओंकार इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा एक है और समस्त संसार उसी की रचना है। जब सृष्टि का रचयिता एक है,तो मनुष्यों के बीच भेदभाव और नफरत का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

गुरु नानक देव जी ने सामाजिक समरसता को केवल उपदेशों तक सीमित नहीं रखा,बल्कि उसे अपने जीवन और व्यवहार में उतारकर दिखाया। उन्होंने जातिगत भेदभाव,छुआछूत और ऊंच-नीच की भावना को मानवता के विरुद्ध बताया। उस दौर में समाज अनेक वर्गों और जातियों में बंटा हुआ था। ऐसे वातावरण में उन्होंने सभी मनुष्यों को समान मानने की शिक्षा दी। उनका संदेश था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके सद्कर्म,सेवा भावना और नैतिक आचरण से निर्धारित होती है। उनकी शिक्षाओं में संगत और पंगत की परंपरा सामाजिक समानता का जीवंत उदाहरण है। संगत में सभी लोग एक साथ बैठकर प्रभु का स्मरण करते हैं,जबकि पंगत और लंगर में बिना किसी जाति,धर्म,वर्ग अथवा आर्थिक भेदभाव के सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं। यह परंपरा आज भी समाज को समानता और भाईचारे का व्यावहारिक संदेश दे रही है। लंगर की व्यवस्था यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा और सम्मान उसके आर्थिक या सामाजिक स्तर से कम नहीं हो सकता।

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं कि नाम जपो, किरत करो और वंड छको। इन तीनों सिद्धांतों में एक आदर्श समाज और संतुलित जीवन की पूरी अवधारणा

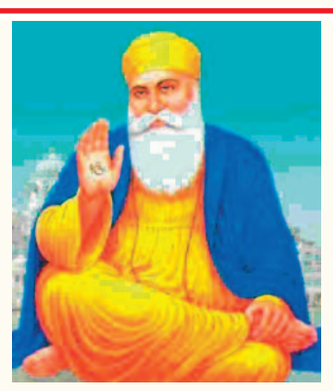

दिखाई देती है। नाम जपो का अर्थ है ईश्वर का स्मरण करना और अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना बनाए रखना। किरत करो का संदेश है कि मनुष्य ईमानदारी और मेहनत से अपनी आजीविका अर्जित करे। वहीं वंड छको का अर्थ है अपनी कमाई और संसाधनों को जरूरतमंदों के साथ बांटना।आज जब समाज में व्यक्तिगत स्वार्थ,आर्थिक असमानता और उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है,तब ये सिद्धांत और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। यदि व्यक्ति ईमानदारी से परिश्रम करे, अपनी आवश्यकताओं के साथ दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान रखे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे,तो अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव है। गुरु नानक देव जी का दर्शन हमें केवल अपने लिए जीने के बजाय दूसरों के सुख-दुःख में सहभागी बनने की प्रेरणा देता है। गुरु नानक देव जी ने धर्म को आपसी संघर्ष का आधार बनाने के बजाय मानव कल्याण का माध्यम माना। उन्होंने धार्मिक कट्टरता,बाहरी दिखावे और पाखंड का विरोध किया। उनके लिए सच्चा धर्म वही था,जो मनुष्य को सत्य, प्रेम,करुणा और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाए। उन्होंने विभिन्न धार्मिक परंपराओं के लोगों से संवाद किया और अपनी यात्राओं के माध्यम से मानवता,सद्भाव तथा नैतिक जीवन का संदेश दिया। वर्तमान समय में दुनिया अनेक प्रकार के तनाव,युद्ध,धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक विभाजन का सामना कर रही है। ऐसे दौर में गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि संवाद, सहिष्णुता और परस्पर सम्मान ही शांतिपूर्ण समाज की आधारशिला हैं। किसी भी धर्म का वास्तविक उद्देश्य मानवता को जोडऩा होना चाहिए, न कि लोगों के बीच दीवारें खड़ी करना।

गुरु नानक देव जी ने सेवा को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना। उनके विचारों में जरूरतमंदों की सहायता,भूखों को भोजन कराना, दुखियों के प्रति संवेदना रखना और समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़ा होना सच्ची मानवता के प्रतीक हैं। सिख परंपरा में दिखाई देने वाली सेवा भावना इसी विचारधारा की निरंतरता है। गुरुद्वारों में चलने वाले लंगर,प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य और जरूरतमंदों की सहायता इसके उदाहरण हैं।आज समाज में अनेक लोग आर्थिक कठिनाइयों, बेरोजगारी,गरीबी और सामाजिक असमानता से जूझ रहे हैं। ऐसे में गुरु नानक देव जी की सेवा और साझा जिम्मेदारी की शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि समाज के संपन्न और सक्षम वर्ग को जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। सामाजिक समरसता केवल भाषणों और आयोजनों से स्थापित नहीं होती,बल्कि इसके लिए व्यवहार में समानता,सहयोग और संवेदनशीलता लानी पड़ती है।

आज भारत विविधताओं से भरा देश है। यहां अलग-अलग धर्म,भाषाएं, जातियां,संस्कृतियां और परंपराएं एक साथ मौजूद हैं। यही विविधता हमारी पहचान और शक्ति है। लेकिन जब जातीय भेद-भाव,धार्मिक कटुता,सामाजिक असमानता और आपसी अविश्वास बढ़ता है,तब राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव प्रभावित होते हैं। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।उनकी शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है,जब प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, समान अवसर और न्याय मिले। सामाजिक समरसता का अर्थ केवल एक साथ रहना नहीं,बल्कि एक-दूसरे के अधिकारों,भावनाओं और अस्तित्व का सम्मान करना भी है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव करना मानवता के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। गुरु नानक जयंती केवल धार्मिक उत्सव या औपचारिक आयोजन का अवसर नहीं है। यह आत्मचिंतन का दिन भी है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में कीर्तन,अरदास,प्रभात फेरियां और लंगर के आयोजन होते हैं। इन आयोजनों की वास्तविक सार्थकता तभी है,जब हम गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं।

होटलों की आड़ में चल रहा है देह व्यापार

कानून सो रहा है, कारोबार फल रहा है!

शहरों की चमकती सड़कों, आलीशान होटलों और आधुनिक जीवनशैली के बीच यदि शोषण का कारोबार फलने-फूलने लगे,तो विकास के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। होटल यात्रियों के ठहरने, पर्यटन, व्यापार और पारिवारिक आवागमन की सुविधा के लिए होते हैं,लेकिन यदि कहीं उनकी आड़ में देह व्यापार, मानव तस्करी और महिलाओं का शोषण चल रहा है,तो यह केवल एक अवैध गतिविधि नहीं,बल्कि कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही की गंभीर विफलता है। सवाल यह है कि शहरों में ऐसे कारोबार पनपने की परिस्थितियाँ आखिर बनती कैसे हैं और जिम्मेदार तंत्र समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करता? होटल व्यवसाय शहरों की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे रोजगार मिलता है, पर्यटन बढ़ता है और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलती है। लेकिन व्यवसाय की आड़ में गैरकानूनी गतिविधियों को संरक्षण देने वाले प्रतिष्ठान पूरे होटल उद्योग की प्रतिष्ठा को बदनाम करते हैं। यदि किसी होटल में देह व्यापार या शोषण का संगठित कारोबार संचालित हो रहा है,तो उसके विरुद्ध कार्रवाई केवल दिखावे की नहीं,बल्कि निर्णायक होनी चाहिए। कुछ समय के लिए छापेमारी करके फिर सब कुछ सामान्य हो जाना प्रशासनिक सफलता नहीं कहलाता। सबसे बड़ा प्रश्न पुलिस और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता पर है। यदि किसी इलाके में संदिग्ध गतिविधियाँ लगातार सामने आती हैं,शिकायतें होती हैं और फिर भी कारोबार चलता रहता है,तो व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है। क्या निरीक्षण नियमित होते हैं? क्या शिकायतों की जाँच निष्पक्षता से की जाती है? क्या होटल संचालकों की जिम्मेदारी तय होती है? क्या अपराध के पीछे सक्रिय दलालों और संगठित नेटवर्क तक कार्रवाई पहुँचती है? जनता को केवल छापेमारी की तस्वीरें नहीं,बल्कि अपराध पर स्थायी नियंत्रण दिखाई देना चाहिए।



डॉ.सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

देह व्यापार से जुड़े मामलों को केवल नैतिकता के चश्मे से देखना भी गंभीर भूल है। कई महिलाएँ आर्थिक मजबूरी,धोखाधड़ी,दबाव,हिंसा और मानव तस्करी के कारण शोषण की परिस्थितियों में फँस जाती हैं। ऐसी महिलाओं को अपमानित करना या अपराधी की तरह प्रस्तुत करना अन्याय है। कार्रवाई उन लोगों के विरुद्ध होनी



चाहिए जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं,महिलाओं को नियंत्रित करते हैं,उन्हें धमकाते हैं और शोषण से मुनाफा कमाते हैं। नाबालिगों के यौन शोषण के मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई और तत्काल संरक्षण अनिवार्य है। समाज की विडंबना देखिए कि ऐसे मामलों में अक्सर महिला की पहचान,चरित्र और निजी जीवन चर्चा का विषय बन जाता है,जबकि कारोबार चलाने वाले,पैसे कमाने वाले और संभावित संरक्षण देने वाले लोग पर्दे के पीछे रह जाते हैं। पीड़ित को बदनाम करना आसान है, लेकिन अपराध के नेटवर्क तक पहुँचना कठिन। यही मानसिकता शोषण को बढ़ावा देती है। जब समाज पीड़ित पर प्रश्न उठाता है और अपराधी के तंत्र पर चुप रहता है,तब उसकी चुप्पी भी अन्याय की ताकत बन जाती है।

होटल संचालकों की जिम्मेदारी भी स्पष्ट होनी चाहिए। व्यवसाय चलाने का अधिकार कानून के पालन के साथ जुड़ा है। पहचान संबंधी नियमों, रिकॉर्ड,सुरक्षा व्यवस्था और वैधानिक संचालन में लापरवाही को सामान्य नहीं माना जा सकता। किसी प्रतिष्ठान के विरुद्ध बार-बार शिकायत मिलने पर उसकी गंभीर जाँच होनी चाहिए। लाइसेंस और संचालन नियमों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा दोषी पाए जाने पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई हो। रसूख, आर्थिक प्रभाव या राजनीतिक संपर्क किसी भी व्यवसाय को कानून से ऊपर नहीं बना सकते। हालाँकि, कार्रवाई के नाम पर निर्दोष नागरिकों के निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप भी स्वीकार्य नहीं है। होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखना,बिना प्रमाण आरोप लगाना या नैतिक पुलिसिंग करना कानून का उद्देश्य नहीं हो सकता। कार्रवाई प्रमाण आधारित, निष्पक्ष और संवेदनशील होनी चाहिए। प्रशासन का लक्ष्य अपराध रोकना, शोषण के शिकार लोगों को सुरक्षित करना और दोषियों को न्याय के कटघरे तक पहुँचाना होना चाहिए। मानव तस्करी और यौन शोषण के मामलों में पुलिस,महिला एवं बाल संरक्षण इकाइयों,सामाजिक संस्थाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और पुनर्वास केंद्रों के बीच समन्वय आवश्यक है। पीड़ितों को सुरक्षित आश्रय, कानूनी सहायता, मानसिक परामर्श और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए। केवल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ाना सफलता नहीं है;सफलता तब है जब शोषण का नेटवर्क टूटे,पीड़ित सुरक्षित हों और अपराध दोबारा न पनपे।

शहरों का विकास केवल ऊँची इमारतों, चमकदार बाजारों और बढ़ते होटल व्यवसाय से नहीं मापा जा सकता। जिस शहर में महिलाओं की सुरक्षा कमजोर हो, कानून प्रभावहीन हो और अपराधियों को संरक्षण मिलने की आशंका हो,वहाँ विकास की चमक खोखली है। प्रशासन को नियमित निरीक्षण,शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि कानून अपराधियों के लिए भय और पीड़ितों के लिए सुरक्षा का माध्यम है।

होटल व्यवसाय पर्यटन और रोजगार का माध्यम बने,अपराध का आवरण नहीं। देह व्यापार की आड़ में शोषण,मानव तस्करी और महिलाओं की मजबूरी का व्यापार किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। यदि अपराध खुलेआम फलता है और प्रशासन केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित रहता है,तो सवाल उठेंगे ही। कानून की नींद अपराधियों के लिए अवसर बन जाती है और प्रशासन की चुप्पी जनता के विश्वास को कमजोर करती है। शहरों के होटल सुरक्षित ठहराव के केंद्र बनें,शोषण के ठिकाने नहीं—यही सभ्य समाज और जवाबदेह शासन की कसौटी है।

जीवन का सच समय की गति, नश्वर संसार और दिलों की दुनिया

समय किसी के लिए नहीं रुकता वह बिना किसी आहट के लगातार आगे बढ़ता रहता है और हर बीतते दिन के साथ हमें इस सच्चाई के क़रीब ले जाता है कि इंसान इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है तस्वीर में लिखा गया यह संदेश कि आने वाले समय में हम में से कोई भी इस दुनिया में नहीं रहेगा क़ब्रें शायद गुमनाम हो जाएंगी और समय की धूल बहुत से निशानों को मिटा देगी देखने में एक कड़वी सच्चाई लगता है लेकिन गहराई से सोचें तो यही जीवन का सबसे बड़ा सच है जब हम इस अंतिम पड़ाव को सामने रखकर आज की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमारे बहुत से अहंकार झगड़े और बेमतलब की दौड़ अपने आप महत्वहीन लगने लगती है

समय का आईना और इंसान की हक़ीक़त,

इंसान अक्सर यह मान बैठता है कि उसकी मौजूदगी ताक़त शोहरत या धन दौलत हमेशा बनी रहेगी लेकिन इतिहास और समय दोनों इस बात के गवाह हैं कि बड़े बड़े नाम ऊंची इमारतें और शानदार महफ़िलों के निशान भी समय के लंबे सफ़र में धुंधले पड़ जाते हैं हम इस दुनिया में बस थोड़े से समय के मुसाफिर हैं जब यह एहसास दिल में जागता है तो इंसान को अपनी हैसियत और जिम्मेदारी का सही अंदाज़ा होता है वह समझ जाता है कि असली दौलत वह नहीं है जिसे इकट्ठा किया जाए बल्कि वह है जिसे बांटा जाए।

ईर्ष्या की निरर्थकता और दूसरों के दुःख का एहसास,

इस छोटी सी उम्र में सबसे बड़ी नादानी दूसरों से जलना दिलों में बैर पालना और दूसरों की खुशियों को देखकर कुढ़ना है हम अक्सर किसी की बाहरी खुशी या कामयाबी देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि उस व्यक्ति के हिस्से में कितने दुख अकेलेपन और आज़माइशें लिखी हैं हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और हर किसी के भीतर कोई न कोई अनकही कहानी छिपी होती है इसलिए दूसरों की खुशी पर खुश होना और उनके दुःख दर्द को समझना ही इंसानियत और बड़े दिल की पहचान है।

क्षमा प्रेम और सुकून की विरासत,

अगर हम जानते हैं कि दुनिया के बहुत से निशान मिट जाएंगे तो सवाल यह है कि क्या बाक़ी रहेगा बाक़ी रहती हैं वे मोहब्बतें जो हमने बांटीं वे सहारे जो हमने मुश्किल वक्त में दिए वे माफियां जिन्होंने रिश्तों को बचाया और वह सुकून जो हमारी बातों या मौजूदगी से दूसरों को मिला जीवन के ये कुछ दिन अगर हम शांति नरमी और माफ़ करने के जज्बे के साथ बिता लें तो यही हमारी सबसे क़ीमती कमाई है जब इंसान दुनिया से जाता है तो पत्थरों या निशानों से ज़्यादा लोगों के दिलों में बचा हुआ एहसास उसे जिंदा रखता है। जिंदगी की असली खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हमने कितना लंबा सफर तय किया बल्कि इसमें है कि इस सफ़र में हम कितने अच्छे हमसफ़र साबित हुए।

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़
हरदा,मध्य प्रदेश

समय बड़ा बलवान,समय की बचत धन की बचत है...

मनुष्य के जीवन में यदि कोई वस्तु सबसे मूल्यवान,सबसे निष्पक्ष और सबसे क्रूर है तो वह है समय। धन खोकर कमाया जा सकता है,स्वास्थ्य खोकर लौटाया जा सकता है,संबंध टूट कर जुड़ सकते हैं,पर बीता हुआ एक क्षण कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने समय को ही सबका राजा कहा है,क्योंकि समय किसी का मित्र नहीं,किसी का शत्रु नहीं। वह राजा और रंक दोनों को दिन के चौबीस घंटे ही देता है,अंतर केवल इतना है कि कोई उसे सोने में गंवा देता है और कोई उसी में इतिहास रच देता है। इस सत्य को तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही कह दिया था, समय चुकि पुनि का पछताने,का वर्षा जब कृषि सुखाने। अर्थात समय चूक जाने पर पछताने से क्या लाभ,जब फसल सूख चुकी हो तब वर्षा का क्या अर्थ। गीता में भगवान श्रीकृष्ण स्वयं को काल बताते हुए कहां है

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो,

अर्थात मैं ही महाकाल हूँ,लोकों का नाश



करने वाला। जो समय की गति को समझ लेता है,वही जीवन को समझ लेता है। समय की बचत ही वास्तव में धन की बचत है,बल्कि धन से भी बड़ी बचत है। अंग्रेजी में कहा जाता है टाइम इज मनी,परभारतीय दर्शन कहता है टाइम इज मोर दैन मनी। पैसा बैंक में जमा होता है,पर समय केवल खर्च होता है,वह कभी जमा नहीं होता।

बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1748 में अपने युवा व्यापारियों को लिखे पत्र में कहा था,याद रखो समय धन है, जो व्यक्ति दिन में दस शिलिंग कमा सकता है और आधा दिन घूमने में बिता देता है, वह केवल छह पेंस खर्च नहीं करता, बल्कि पाँच शिलिंग गंवा भी देता है। आज के जीवन में यह बात और भी स्पष्ट है। एक युवा यदि रोज एक घंटा सोशल मीडिया पर व्यर्थ स्क्रॉल करता है तो साल में तीन सौ पैंसठ घंटे, यानी पंद्रह पूरे दिन वह केवल अंगूठा चलाता है। यदि वही एक घंटा वह कोई कौशल सीखने में लगाए तो तीन साल में वह किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ बन सकता है। यही समय का चक्रवृद्धि ब्याज है।

कबीरदास जी ने इसी बात को सरल शब्दों में कहा है...

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,पल में प्रलय होएगी,बहुरि करेगा कब।

जो काम कल पर टालते हैं,वे जीवन भर कल पर ही रह जाते हैं। विद्यार्थी सोचता है परीक्षा के समय पढ़ लूंगा, किसान सोचता है कल बोऊंगा, व्यापारी सोचता है कल निवेश करूंगा, पर समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। महापुरुषों ने समय को हमेशा ईश्वर से भी बड़ा माना है। स्वामी विवेकानंद युवाओं से कहते थे,उठो,जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए, वे कहते थे एक मिनट भी बर्बाद मत करो,तुम्हारे पास अनंत शक्ति है पर समय सीमित है। महात्मा गांधी समय के इतने पाबंद थे कि लोग उनकी घड़ी देखकर अपनी घड़ी मिलाते थे,उनका कहना था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है और उनका हर क्षण नियोजित था। एक बार किसी मिलने वाले ने पाँच मिनट की देरी कर दी तो गांधी जी ने कहा, आपने मेरे पाँच मिनट ही नहीं, पाँच मिनट में होने वाले मेरे विचार भी छीन लिए।

रोमन दार्शनिक सेनेका ने कहा है, जीवन छोटा नहीं है,हम ही उसे छोटा बना देते हैं,हमारे पास समय की कमी नहीं है,हम ही उसे गंवाते हैं। गुरुनानक देव जी की वाणी है...

नानक समय दी कदर कर,समय बड़ा अनमोल,जे समय चूके बंदेया,फिर पछताएगा तू।

फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने भी कहा था...

समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करना है, क्योंकि समय ही तो जीवन है।

समय का मूल्य समझाने के लिए इतिहास और वर्तमान में कई सशक्त उदाहरण हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम सुबह चार बजे उठ जाते थे,वे कहते थे सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं,सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। उन्होंने कहा था एक मिनट की देरी से रॉकेट नहीं,राष्ट्र का भविष्य चूक जाता है। उनकी समयनिष्ठा ने ही भारत को मिसाइल शक्ति बनाया। दूसरा उदाहरण टाइटैनिक का है,चौदह अप्रैल उन्नीस सौ बारह को टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर को पास के जहाज कैलिफोर्नियन से बर्फ की चट्टान की चेतावनी मिली थी,पर वह थका हुआ था और उसने संदेश को गंभीरता से नहीं लिया,दस मिनट बाद जवाब देने की सोची। वही दस मिनट की देरी ने पंद्रह सौ लोगों की जान ले ली,समय पर लिया गया एक संदेश इतिहास बदल देता। इसलिए समय का सदुपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी कला है।

संजीव ठाकुर,रायपुर,छत्तीसगढ़,

जनहित की प्रयोगशाला में पिसता आम आदमी

लोककल्याण की चौखट पर दम तोड़ती उम्मीदें... जनता के नाम पर जश्न, जनता के हिस्से में जद्दोजहद!

सरकारी योजना का सबसे चमकदार हिस्सा उसका विज्ञापन होता है और सबसे धुंधला हिस्सा उसका लाभार्थी। दीवारों पर बड़े-बड़े अक्षरों में उपलब्धियां दर्ज हो जाती हैं,मंचों से आंकड़ों की आतिशबाजी होती है,अखबारों में सफलता की तस्वीरें छपती हैं,मगर उसी योजना का कोई वास्तविक हकदार जब अपने हिस्से का लाभ मांगने निकलता है तो उसे दफ्तरों की चौखट,दस्तावेजों की गठरी और तारीखों के फेर में उलझा दिया जाता है। विडंबना देखिए,जिसके नाम पर पूरी व्यवस्था खड़ी की जाती है,कई बार वही व्यक्ति उसके दरवाजे पर सबसे कम अधिकार वाला साबित होता है। यह महज प्रशासनिक खामी नहीं,जनकल्याण के दावों और उनकी जमीनी हकीकत के बीच बढ़ती खाई का सवाल है।



रितेश कुमार जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

देश में योजनाओं की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना,आयुष्मान भारत,उज्ज्वला,किसान सम्मान निधि और मनरेगा जैसी योजनाओं का दायरा व्यापक है। इनके पीछे गरीब को आवास,मरीज को इलाज,परिवार को रसोई गैस,किसान को आर्थिक सहारा और ग्रामीण श्रमिक को रोजगार देने की मंशा है। बजट में इनके लिए प्रावधान होते हैं,प्रचार में इन्हें सरकार की उपलब्धि बताया जाता है। लेकिन किसी योजना की असली सफलता इस बात से तय नहीं होती कि उसकी घोषणा कितने बड़े मंच से हुई, बल्कि इससे तय होती है कि उसका लाभ कितने जरूरतमंदों तक पहुंचा। जिस गरीब को आवास का इंतजार है,उसके लिए योजना का नाम नहीं,सिर पर छत मायने रखती है। बीमार के लिए सरकारी दावा नहीं,समय पर इलाज जरूरी है। किसान के लिए भाषण नहीं,खाते में सहायता और खेत में राहत का महत्व है। जनकल्याण की परीक्षा यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले उन कागजी पहाड़ों को देखना चाहिए,जिन्हें पार किए बिना नागरिक का हक आगे नहीं बढ़ता। योजनाएं ऊपर बनती हैं,लेकिन नीचे पहुंचते-पहुंचते नियमों और औपचारिकताओं का ऐसा जाल बिछ जाता है कि जरूरतमंद रास्ता ही भूल जाता है। एक प्रमाण-पत्र के लिए दूसरा प्रमाण-पत्र,सत्यापन के लिए नया आवेदन और आवेदन के बाद अगली तारीख। फाइलें विभागों के बीच यात्रा करती रहती हैं,लेकिन लाभार्थी की परेशानी अपनी जगह खड़ी रहती है। रोज कमाकर खाने वाले व्यक्ति से यह उम्मीद करना कि वह कई दिन मजदूरी छोड़कर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए, व्यवस्था की संवेदनहीनता है। इस जटिलता का फायदा वे लोग उठाते हैं, जिनकी पहुंच और पहचान है। जहां नागरिक का अधिकार प्रक्रिया का मोहताज बन जाए,वहां बिचौलियों की दुकान अपने आप खुल जाती है।

डिजिटल व्यवस्था ने सुविधाओं के नए दरवाजे जरूर खोले हैं,लेकिन यह भी सच है कि देश का हर नागरिक उन दरवाजों तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। एक ओर डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों का बखान है,दूसरी ओर गांवों में इंटरनेट, स्मार्टफोन और तकनीकी समझ का अभाव है। जिस व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना ही नहीं आता,उसके लिए डिजिटल सुविधा भी एक नई दीवार बन जाती है। योजनाओं की जानकारी होर्डिंग्स और विज्ञापनों में दिखाई देती है,लेकिन अंतिम छोर पर रहने वाले पात्र व्यक्ति तक उसका संदेश नहीं पहुंचता। अधूरी जानकारी,अशिक्षा और अफवाहें इस दूरी को और बढ़ाती हैं। सवाल यह है कि सरकार तकनीक को नागरिक के अनुकूल बना रही है या नागरिक को तकनीक के सामने असहाय छोड़ रही है? डिजिटल सुविधा का अर्थ तभी है,जब वह उस व्यक्ति तक भी पहुंचे जिसके पास साधन सबसे कम हैं। इसके बाद आता है भ्रष्टाचार और लापरवाही का वह हिस्सा, जिस पर अक्सर उपलब्धियों के शोर में पर्दा पड़ जाता है। बजट आवंटित होता है,लेकिन उसके इस्तेमाल की निगरानी कितनी प्रभावी है? निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री, लाभार्थियों की सूची में हेरफेर,अपात्रों को प्राथमिकता और वास्तविक जरूरतमंदों का नाम गायब होना योजनाओं की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाते हैं। आधार और बैंक खातों से जुड़ी विसंगतियां भी कई बार पात्र लोगों के भुगतान में बाधा बनती हैं।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

C M Y K

अयोध्या की तर्ज पर सरगुजा के रामगढ़ में आकार ले रहा भव्य श्रीराम मंदिर,पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया निरीक्षण

- धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा ऐतिहासिक रामगढ़: मंत्री राजेश अग्रवाल ने श्रीराम मंदिर निर्माण कार्यों का लिया जायजा
- रामगढ़ को धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने की पहल; गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश





-संवाददाता-
अम्बिकापुर/उदयपुर,23 नवम्बर2026।
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर रामगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड स्थित ऐतिहासिक रामगढ़ में अयोध्या के भव्य श्रीराम मंदिर की तर्ज पर श्रीराम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति,धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज रामगढ़ पहुंचकर निर्माणाधीन मंदिर की प्रगति और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

संकल्प को धरातल पर साकार होते देखना सुखद:निरीक्षण के दौरान मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कुछ समय पूर्व उन्होंने रामगढ़ में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण की घोषणा व भूमिपूजन किया था,आज उस संकल्प को साकार होते देखना अत्यंत सुखद है। यह मंदिर क्षेत्रवासियों की आस्था,विश्वास और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनेगा।

प्राचीन गुफाओं और वनवास काल से जुड़ा है रामगढ़ का इतिहास : श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को भगवान श्रीराम का ननिहाल माना जाता है और वनवास काल के दौरान उनके यहां से गुजरने की लोकमान्यताएं प्रचलित हैं। रामगढ़ पर्वत, सीताबेंगरा व जोगीमारा जैसी प्राचीन गुफाएं और महाकवि कालिदास की साहित्यिक परंपरा इस स्थल को विशिष्ट पहचान देती हैं।

स्थानीय रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा : मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय व्यापारियों व छोटे व्यवसायियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मेडिकल स्टोर की आड़ में बेच रहा था नशीली दवाएं,संचालक गिरफ्तार...

यूपी से लाकर बेचता था प्रतिबंधित कफ सिरप और टैबलेट, आबकारी उडऩदस्ता टीम ने 2 लाख का नशीला पदार्थ किया जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शहर के सुभाषनगर स्थित न्यू अनुष्का मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाओं का कारोबार करने का मामला सामने आया है। संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम ने छापेमारी कर मेडिकल स्टोर के पीछे बने कमरे से प्रतिबंधित कफ सिरप और टैबलेट जब्त की है। जब्त नशीले पदार्थों की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। मामले में मेडिकल स्टोर संचालक राजेश समद्दार को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि 23 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुभाषनगर स्थित न्यू अनुष्का मेडिकल स्टोर से बड़ी मात्रा में नशीली कफ सिरप और टैबलेट बेची जा रही है। सूचना की पुष्टि के लिए टीम ने पहले मेडिकल स्टोर से दवा खरीदवाई। इसकी पुष्टि होने के बाद छापेमारी की गई। इस दौरान मेडिकल स्टोर में कोई मादक पदार्थ नहीं मिला। टीम ने जब दुकान के पीछे बने कमरे की तलाशी ली तो वहां मैगनेट्स कफ सिरप की बोतलें, 75 नग अपकारेस कफ सिरप और 3600 नग प्रतिबंधित टैबलेट मिलीं। टीम ने सभी नशीले पदार्थ जब्त कर संचालक को गिरफ्तार कर लिया।



यूपी से लाकर करता था बिक्री : आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के अनुसार, आरोपी उत्तर प्रदेश से नशीली कफ सिरप और टैबलेट लाकर मेडिकल स्टोर की आड़ में बेचता था। उन्होंने बताया कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अधिक कमाई के लालच में नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले लोग युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में धकेल रहे हैं।

63 वाहन चालकों के कटे चालान,वसूले गए समन शुल्क

ट्रिपल राइडिंग और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों की भी जांच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरगुजा पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाकर 63 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाते मिले चार चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं, दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाने और मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों की भी जांच की गई। पुलिस के अनुसार, सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कोतवाली,गांधीनगर,मणिपुर थाना और यातायात शाखा की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट, वाहन के दस्तावेज और नंबर प्लेट की भी जांच की गई। अभियान के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र में 10 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाने के तीन और मौके पर दस्तावेज पेश नहीं करने के तीन मामले शामिल हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र में आठ प्रकरणों में 3700 रुपए समन शुल्क वसूला गया। मणिपुर थाना क्षेत्र में बिना सीट बेल्ट के तीन,दस्तावेज नहीं होने के पांच और ट्रिपल राइडिंग के दो मामलों में चालानी कार्रवाई की गई। वहीं, यातायात शाखा ने 35 प्रकरणों में 14,900 रुपए समन शुल्क वसूला। इनमें



बिना सीट बेल्ट के 14,वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने के आठ,बिना हेलमेट के पांच और ट्रिपल राइडिंग के तीन मामले शामिल हैं। इसके अलावा मालवाहक में सवारी बैठाने के दो,दस्तावेज नहीं होने के दो और बिना वर्दी वाहन चलाने का एक मामला दर्ज किया गया। सरगुजा पुलिस ने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर ही सडक़ दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

इंजीनियरिंग कॉलेज में आठ दिवसीय यूएचवी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का समापन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबिकापुर में आयोजित आठ दिवसीय यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज (यूएचवी-आईआई) फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का 23 नवंबर को समापन हुआ। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का आठ दिवसीय आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलीटेक्निक संस्थानों और विज्ञान एवं कला महाविद्यालयों के करीब 45 प्राध्यापकों ने हिस्सा लिया।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा के कुलपति प्रो. डॉ. राजेंद्र लकपाले तथा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,भिलाई के कुलसचिव डॉ. राजेश लालवानी थे। इस अवसर पर एआईसीटीई यूएचवी पैनल के प्रो. डॉ. हिमांशु कुमार राय,कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डॉ. रामनारायण खरे,सह-प्रशिक्षक रविशंकर



रजक एवं माया राठौर और पर्यवेक्षक डॉ. शरद गांगेगांवकर उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. डॉ. राजेंद्र लकपाले ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि बेहतर समाज का निर्माण और व्यक्ति में मानवीय मूल्यों का विकास करना भी है। इसके लिए आत्मविश्लेषण जरूरी है, ताकि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और व्यवहार का मूल्यांकन कर संवेदनशील नागरिक बन सके। कुलसचिव डॉ. राजेश लालवानी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,ऑटोमेशन और तकनीकी नवाचार के बढ़ते दौर में तकनीकी दक्षता के साथ मानवीय मूल्यों का समन्वय जरूरी है। तकनीक का उपयोग समाज के कल्याण, सुरक्षा और विकास के लिए होना चाहिए। वहीं, प्रो. डॉ. हिमांशु कुमार राय ने परिवार, समाज और प्रकृति के साथ संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। 16 से 23 नवंबर तक चले प्रशिक्षण में आत्म-अन्वेषण, स्वयं और शरीर के बीच संबंध, परिवार में विश्वास एवं सम्मान, सामाजिक समरसता, प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व और मूल्य आधारित शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की गई। वीडियो प्रस्तुतियों, संवाद, ट्यूटोरियल, समूह गतिविधियों और व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से प्रतिभागियों को इन विषयों की समझ विकसित करने का अवसर मिला। प्राचार्य प्रो. डॉ. रामनारायण खरे ने आठ दिनों के प्रशिक्षण का सार प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें प्राप्त समझ को शिक्षण कार्य,व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक व्यवहार में अपनाना जरूरी है। प्रतिभागियों ने भी अपने अनुभव और सीख साझा किए। उन्होंने अपने-अपने संस्थानों में मानवीय मूल्यों पर आधारित शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने का संकल्प लिया।

अभिरुचि केंद्र में 1 दिसंबर से शुरू होगा सिलाई प्रशिक्षण

महिलाओं और बालिकाओं के लिए चार माह का सर्टिफिकेट कोर्स, 25 नवंबर से मिलेंगे प्रवेश फार्म



-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर के शिवाजी पार्क स्थित गुदरी चौक में सेवा किटी समूह द्वारा संचालित अभिरुचि केंद्र में 1 दिसंबर से महिलाओं और बालिकाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। जन शिक्षण संस्थान, सरगुजा के सहयोग से चार माह का सर्टिफिकेट कोर्स संचालित होगा। प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए 25 नवंबर से अभिरुचि केंद्र में फार्म उपलब्ध रहेंगे। इच्छुक महिलाएं और बालिकाएं प्रतिदिन दोपहर 3 से 4 बजे के बीच केंद्र पहुंचकर प्रवेश फार्म प्राप्त कर सकती हैं। केंद्र में 1 दिसंबर से अन्य गतिविधियां भी शुरू होंगी। इनकी समय-सारिणी केंद्र से प्राप्त की जा सकती है। प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए दीपमाला सिंह, ज्योति द्विवेदी, स्मिता तिवारी, मिलन शर्मा,रेणुका उपाध्याय,श्रद्धा खेरपांडे,सुधा तिवारी और अनिता शुक्ला से संपर्क किया जा सकता है।

स्कॉर्पियो से 22.8 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त,दो आरोपी गिरफ्तार

खैरबार रोड पर ग्राहक तलाश रहे थे आरोपी,शराब और वाहन समेत 10 लाख रुपए का मशरूका जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

शहर में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्कॉर्पियो वाहन में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब रखकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 22.800 लीटर अंग्रेजी शराब और स्कॉर्पियो जब्त की है। जब्त मशरूके की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, 21 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खैरबार रोड पर गाड़ाघाट से आगे सफेद स्कॉर्पियो क्रमांक सीजी 15 डीएक्स 7048 में दो युवक अवैध अंग्रेजी शराब लेकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने ग्राम खैरबार में घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका। पूछताछ में आरोपियों की पहचान रितेश राजवाड़े (26) और ठाकुर प्रसाद राजवाड़े (20), निवासी भिट्ठीकला मांझापारा, थाना मणिपुर के रूप में हुई। वाहन की तलाशी लेने पर दो कार्टून में



अलग-अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब मिली। इसमें कंगारू 10000 स्ट्रॉन्ग बीयर की 24 बोतलें (15.6 लीटर), ग्रीन लेबल व्हिस्की के 10 पाव (1.8 लीटर), फ्रंट लाइन व्हिस्की के 10 पाव (1.8 लीटर) और गोवा स्पेशल व्हिस्की के 20 पाव (3.6 लीटर) शामिल हैं। कुल 22.8 लीटर शराब जब्त की गई। आरोपी शराब के परिवहन और बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 816/26, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया।

इनकी रही कार्रवाई में भूमिका

कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सुमेश सिंह, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, मुकेश गुप्ता तथा आरक्षक केसरी सोनी, सुरेश गुप्ता, अमरेश दास, संजीव चौबे, संजीव पाण्डेय और अभिषेक सिंह शामिल रहे।

कृषि महाविद्यालय में उत्तर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ

तीन दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न कृषि महाविद्यालयों के खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा,24 नवंबर तक होंगे मुकाबले

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, अंबिकापुर में रविवार को उत्तर क्षेत्रीय अंतर महाविद्यालयीन खेल-कूद प्रतियोगिता-2026 का शुभारंभ हुआ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत आयोजित यह तीन दिवसीय प्रतियोगिता 22 से 24 नवंबर तक चलेगी। इसमें विभिन्न कृषि महाविद्यालयों के विद्यार्थी अलग-अलग खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयुक्त एवं उप संचालक कृषि सरगुजा पीएस दीवान तथा विशिष्ट अतिथि जिला क्रीड़ा अधिकारी रामकुमार सिंह थे। अध्यक्षता महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एसके सिन्हा ने की। इस अवसर पर सह-संचालक अनुसंधान डॉ. केएल पैकरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं आलू अनुसंधान केंद्र मैनपाट के प्रमुख डॉ. पीके भगत तथा कृषि महाविद्यालय शंकरगढ़ के अधिष्ठाता डॉ. जीपी पैकरा उपस्थित रहे। अतिथियों ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन,आत्मविश्वास,नेतृत्व क्षमता और टीम भावना को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने खिलाडियों को खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी सहयोग और खेल भावना को बढ़ावा देना है। आयोजन में महाविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारी-कर्मचारी और छात्र-छात्राएं शामिल हुए। प्रतियोगिता के सफल संचालन में क्रीड़ा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार नायक और कृषि सांख्यिकी की प्राध्यापक डॉ. नीलम चौकसे का योगदान रहा।



मितानिन दिवस पर शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पुलिस लाइन में मितानिनों का सम्मान

स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने में मितानिनों की भूमिका सराहनीय : सीएमएचओ डॉ. जगसाय सरूता

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

मितानिन दिवस के अवसर पर 23 नवम्बर को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पुलिस लाइन, अम्बिकापुर में कार्यक्रम आयोजित कर मितानिनों के योगदान की सराहना की गई तथा उन्हें शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जगसाय सरूता, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीसी. पैकरा, डॉ. पी.के. सिन्हा (डीएनओ-एनएलईपी), डॉ. शीला नेताम (यूसीएचसी प्रभारी), डॉ. सीमा तिग्गा (डीएम-अर्बन), डॉ. उत्कर्ष सोनी (शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पुलिस लाइन प्रभारी), श्री अनिल पाण्डेय, श्री



धनेश प्रताप (सुपरवाइजर), मितानिन प्रशिक्षक, मितानिन सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मितानिनों की स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उनके समर्पण एवं सेवा भावना की सराहना की गई। मितानिन शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता तथा शासन की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके निरंतर प्रयासों से समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ रहा है और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जगसाय सरूता ने मितानिनों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने में मितानिनों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर डॉ. जगसाय सरूता द्वारा समस्त मितानिनों को शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया तथा उनके समर्पण, सेवाभाव एवं निरंतर प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

विभागीय जांच की प्रक्रिया एवं नियमों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

जांच प्रकरणों के नियमानुसार,पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण पर दिया गया मार्गदर्शन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,23 नवम्बर 2026
(घटती-घटना)।

विभागीय जांच की प्रक्रिया एवं नियमों की जानकारी देने और जांच प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज 23 नवंबर 2026 को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर के सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिले के सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं 35 प्राचार्य शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री संजय सिंह एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विश्रामपुर, जिला सूरजपुर के प्राचार्य श्री आशीष भट्टाचार्य ने विभागीय जांच की प्रक्रिया, नियमों एवं विभिन्न चरणों के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यशाला में आरोप पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का परीक्षण, अभिलेख एवं दस्तावेजों का संकलन, साक्ष्यों की जांच, संबंधित पक्षों के कथन दर्ज करने तथा जांच प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों की जानकारी दी गई। विषय विशेषज्ञों ने प्रारंभिक जांच, निर्धारित नियमों के अनुरूप विभागीय कार्यवाही,आरोपों का साक्ष्य आधारित परीक्षण, अभिलेखों का विधिवत संधारण,निष्पक्षता के साथ साक्ष्यों एवं कथनों की जांच तथा समय-सीमा में त्रुटिरहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। लंबित विभागीय जांच प्रकरणों के प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। कार्यशाला के अंत में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय जांच की प्रक्रिया को गंभीरता से समझने तथा किसी भी प्रकार की शंका का विषय विशेषज्ञों के माध्यम से समाधान प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विभागीय कार्यवाही में पारदर्शिता,निष्पक्षता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए नियमों के प्रभावी पालन को बढ़ावा देना है।





सोनहत के वनांचल में दाने-दाने को मोहताज 'राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र'!

उज्ञाव और सिंघोर के पण्डो परिवारों के सामने गहराया भोजन का संकट

राशन के लिए दुकान पहुंचीं बुजुर्ग महिलाएं खाली झोला लेकर लौटने को मजबूर,ई-केवाईसी और राशन कार्ड नंबर की तकनीकी उलझन बनी परेशानी

-राजन पाण्डेय-

सोनहत (कोरिया),23 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

विकास के बड़े-बड़े दावों और सरकारी योजनाओं के प्रचार के बीच सोनहत विकासखंड के दूरस्थ वनांचल ग्राम उज्ञाव और सिंघोर से सामने आई तस्वीर सरकारी व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े करती है, विशेष पिछड़ी पण्डो जनजाति के जिन परिवारों को सम्मानपूर्वक 'राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र' कहा जाता है, आज उन्हीं परिवारों के सामने दो वक्त के भोजन का संकट गहराता दिखाई दे रहा है, हालात ऐसे हैं कि राशन की उम्मीद लेकर दुकान पहुंच रहीं बुजुर्ग महिलाएं खाली झोला लेकर वापस लौटने को मजबूर हैं, ग्रामीणों के अनुसार,उज्ञाव और सिंघोर के दर्जनों पण्डो परिवारों को सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा है, इनमें कई बुजुर्ग और असहाय महिलाएं भी शामिल हैं,राशन लेने पहुंचने पर कुछ लोगों को राशन नहीं मिलने की बात कहकर लौटा दिया गया,वहीं कुछ ग्रामीणों को उनके नाम कटने की जानकारी दी गई, हालांकि, वास्तव में किन परिवारों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं और किनका राशन तकनीकी कारणों से रुका है,यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इन परिवारों के घरों तक अनाज नहीं पहुंचना सबसे गंभीर चिंता का विषय है।

न रोजगार का सहारा,न राशन की गारंटी-पण्डो परिवारों की परेशानी केवल सरकारी राशन तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों के सामने रोजगार का संकट भी बना हुआ है, मनरेगा के काम बंद होने और अन्य रोजगारमूलक गतिविधियों की कमी के कारण मजदूरी से होने वाली आय का सहारा भी प्रभावित है,ऐसे में जब परिवारों को उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाला अनाज भी नहीं मिल रहा, तो उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, वनांचल के इन गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए सरकारी राशन केवल एक योजना का लाभ नहीं, बल्कि रोजमर्रा के भोजन का महत्वपूर्ण आधार है, इस आधार के बाधित होने से परिवारों के सामने भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। सबसे अधिक चिंता बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को लेकर है।

शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण,जन सहयोग समिति ने उठाई आवाज-राशन नहीं मिलने की परेशानी से जूझ रहे ग्रामीणों ने अपनी व्यथा कोरिया जन सहयोग समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े के सामने रखी,ग्रामीणों की समस्या सुनने और उनकी स्थिति को गंभीरता से लेने के बाद राजवाड़े ने तत्काल उच्च अधिकारियों से संपर्क कर मामले को उनके संज्ञान में लाने की बात कही,उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पण्डो जनजाति के परिवारों के सामने भोजन का संकट उत्पन्न होना बेहद दुःखद और चिंताजनक है,वे इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और प्रभावित परिवारों को उनका हक दिलाने के लिए त्वरित निराकरण का प्रयास करेंगे,किसी भी गरीब परिवार को उसके अधिकार से वंचित नहीं रहने दिया जाना चाहिए।

प्रशासन से जवाब जरूरी: कब मिलेगा परिवारों को उनका राशन?- इस पूरे मामले में अब प्रशासन के सामने कई अहम सवाल हैं, उज्ञाव और सिंघोर में कितने पण्डो परिवारों को राशन नहीं मिला है? किन हितग्राहियों का ई-केवाईसी अधूरा है? किनके राशन कार्ड नंबर बदले हैं? क्या किसी परिवार का नाम वास्तव में राशन सूची से काटा गया है और यदि ऐसा हुआ है तो किस आधार पर? प्रभावित परिवारों को तत्काल राशन उपलब्ध कराने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? इन सवालों का जवाब केवल कागजी जांच से नहीं,बल्कि गांवों तक पहुंचकर वास्तविक स्थिति का पता लगाने से मिलेगा, प्रशासन को चाहिए कि संबंधित विभाग की टीम भेजकर प्रभावित परिवारों की सूची तैयार करे,ई-केवाईसी और राशन कार्ड नंबर की त्रुटियों को तत्काल सुधारे तथा पात्र परिवारों को बिना अनावश्यक देरी के राशन उपलब्ध कराए,विकास की असली कसौटी योजनाओं के आंकड़े और घोषणाएं नहीं,बल्कि यह है कि उनका लाभ समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं,सोनहत के वनांचल में पण्डो परिवारों के सामने खड़ा भोजन का संकट इसी कसौटी पर व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर रहा है, अब देखना होगा कि प्रशासन इन परिवारों की पुकार सुनकर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है, या फिर इनकी भूख ई-केवाईसी और राशन कार्ड नंबर की तकनीकी उलझनों में ही उलझी रह जाती है।

ई-केवाईसी और बदले राशन कार्ड नंबर की उलझन-

मामले में जनपद पंचायत स्तर पर संपर्क करने पर जानकारी मिली कि कुछ ग्रामीणों का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, जबकि कुछ लोगों के राशन कार्ड नंबर बदल गए हैं, नए नंबर की जानकारी या तकनीकी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण राशन वितरण प्रभावित होने की बात सामने आई है, यहां सवाल केवल तकनीकी खामी का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की जवाबदेही का भी है, जिसके तहत दूरस्थ वनांचल में रहने वाले अशिक्षित अथवा तकनीकी जानकारी से वंचित हितग्राहियों को स्वयं ऑनलाइन प्रक्रियाओं और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिन लोगों के लिए राशन सबसे बड़ी जरूरत है, उन्हीं को राशन पाने के लिए तकनीकी औपचारिकताओं में उलझना पड़ रहा है, यदि ई-केवाईसी अधूरा है या राशन कार्ड का नंबर बदल गया है, तो संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रभावित परिवारों की पहचान कर उनकी समस्या का समाधान कराएं, किसी तकनीकी प्रक्रिया की कमी के कारण जरूरतमंद परिवारों को भोजन से वंचित नहीं रहने दिया जाना चाहिए।

मुखर्जी कॉलोनी में सीसी रोड का भूमिपूजन, समस्याओं के निराकरण के निर्देश

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,23 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

नगर निगम महापौर मंजूषा भगत ने वार्ड क्रमांक 14 के गंगापुर रोड स्थित मुखर्जी कॉलोनी (आदर्श नगर) में सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इसके बाद उन्होंने कॉलोनी में पैदल भ्रमण कर सडक़, नाली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान वार्डवासियों ने अपनी समस्याएं बताईं,जिनके निराकरण के लिए महापौर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। महापौर को अपने बीच पहुंचा देख कॉलोनीवासियों ने प्रसन्नता जताई। स्थानीय लोगों ने कहा कि करीब 15 वर्षों बाद पहली बार किसी महापौर ने गलियों में पैदल घूमकर उनकी समस्याओं को नजदीक से समझने की पहल की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लंबे समय से लंबित समस्याओं का अब निराकरण होगा। कॉलोनीवासियों ने बताया कि वर्ष 2012 से 2015 के बीच हुए विकास कार्यों के बाद सडक़,नाली और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा रखरखाव पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। अब वार्ड में भाजपा पार्षद अनिता रविन्द्र गुप्ता 'भारती' और नगर निगम में भाजपा की सरकार के नेतृत्व में विकास कार्यों की नई पहल शुरू होने की उम्मीद है। महापौर मंजूषा भगत ने लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान वार्ड के नागरिक,महिलाएं,भाजपा कार्यकर्ता तथा नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।



टायर फटने से मौत के मुहाने पर पहुंचे यात्री,पेड़ से भिड़ी बस, 12 घायल

सासाराम से अंबिकापुर आ रही बस का भीषण हादसा,चार गंभीर घायल....

-संवाददाता-

सूरजपुर 23 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

प्रतापपुर-शिवपुर मार्ग पर रविवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, बिहार के सासाराम से यात्रियों को लेकर अंबिकापुर आ रही बस का अचानक टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। दुर्घटना में करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया है,हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई, सूचना मिलते ही प्रतापपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।

शिवपुर मोड़ के पास अचानक फटा बस का टायर- मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सासाराम से यात्रियों को लेकर



शमीम बस क्रमांक सीजी 15 ईए 3408 रविवार को अंबिकापुर के लिए रवाना हुई थी, बस देर रात सेमरसोत होते हुए प्रतापपुर की ओर बढ़ रही थी, इसी दौरान शिवपुर मोड़ के पास अचानक बस का टायर फट गया,टायर फटने के बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई, टक्कर के बाद बस खेत की ओर झुक गई, हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं टक्कर से पेड़ की छाल तक उखड़ गई, अचानक हुए इस हादसे से यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला,बस के भीतर अफरा-तफरी मच गई और घायल यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े।

पुलिस और ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा,घायलों को निकाला बाहर- दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रतापपुर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, स्थानीय ग्रामीणों और अन्य यात्रियों की मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया,इसके बाद डायल 112 और एंबुलेंस की सहायता से घायलों को प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया,अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया,इनमें चार यात्रियों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार प्रतापपुर में जारी रहा, समय रहते पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सका।

हादसे की खबर मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजन-देर रात हुए हादसे की खबर फैलते ही यात्रियों के परिजनों में चिंता और अफरा-तफरी का माहौल बन गया,अंबिकापुर में सूचना पहुंचने के बाद कई परिजन अपने स्वजनों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे,वहीं सुबह दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर भी लोगों की भीड़ जुट गई, हादसे में एक दर्जन यात्रियों के घायल होने की खबर से क्षेत्र में चिंता का माहौल रहा।

जर्जर सड़क के कारण बदले मार्ग से चल रही हैं यात्री बसें- गौरतलब है कि रामानुजगंज-अंबिकापुर मार्ग की जर्जर स्थिति और सड़क निर्माण कार्य जारी होने के कारण इन दिनों यात्री बसें सेमरसोत होते हुए प्रतापपुर मार्ग से अंबिकापुर पहुंच रही हैं, इस वैकल्पिक मार्ग पर यात्री बसों की आवाजाही बढ़ी हुई है,ऐसे में प्रतापपुर-शिवपुर मार्ग पर हुआ यह हादसा यात्री सुरक्षा और सड़क पर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ाता है, हालांकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह बस का टायर फटना बताई जा रही है,लेकिन दुर्घटना की परिस्थितियों की विस्तृत जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी,इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि वैकल्पिक मार्गों से गुजरने वाली यात्री बसों की सुरक्षा, वाहनों की तकनीकी स्थिति और मार्ग पर सावधानी के इंतजामों को लेकर कितनी सतर्कता बरती जा रही है,फिलहाल हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन चार यात्रियों की गंभीर स्थिति और बस के क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है,यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को सड़क की स्थिति और यात्री वाहनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

श्रीमद् भागवत कथा से मिलता है भक्ति, सदाचार और लोककल्याण का संदेश : पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल

लखनपुर के ग्राम गुमगरा कलां में भागवत कथा में शामिल हुए मंत्री राजेश अग्रवाल, प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की

-संवाददाता-

लखनपुर,23 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति,धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल आज सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम गुमगरा कलां में आयोजित पावन श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण कर भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और आराधना में सहभागिता की तथा समस्त प्रदेशवासियों के सुख,शांति,समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ते हैं धार्मिक आयोजन : इस अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जैसे आध्यात्मिक आयोजन भारतीय सनातन संस्कृति,धार्मिक आस्था और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं और उपदेश मानव जीवन को प्रेम,करुणा,सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता को बल मिलता है, साथ ही नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध परंपराओं और संस्कारों से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता है।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध : श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान अपनी समृद्ध धार्मिक परंपराओं और लोक संस्कृति से है। राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अंत में उन्होंने ग्राम गुमगरा कलां में इस भव्य और पावन कथा के सफल आयोजन के लिए आयोजकों व समस्त ग्रामवासियों की सराहना की।







- 2023 में वैकल्पिक व्यवस्था से नियुक्ति, आदेश का पता नहीं
- 2025 में सेवा से पृथक, 2026 में फिर वापसी
- 7 अगस्त को नए कार्यवाही पंजी में बहाली का प्रस्ताव
- 5 सितंबर को अनुपस्थिति अवधि का लाखों का वेतन भुगतान
- आमसभा में विरोध, बेरोजगार युवाओं की शिकायत
- 12 अक्टूबर को फिर पृथक्करण, अब सहकारिता न्यायालय से स्थगन

नियुक्ति से भुगतान तक सवालों का सिलसिला... आखिर अनिल कुमार बनज की भूमिका क्या?

अनिल बनज के दरबार में विवेक की हर गलती माफ! नियुक्ति का नियम अलग,बहाली का रास्ता अलग और वेतन भुगतान का हिसाब भी निराला!

एक कर्मचारी के लिए नए रजिस्टर,नई बैठक और नया सचिव! आखिर विवेक चौरसिया पर इतनी मेहरबानी क्यों?

- अनिल कुमार बनज की भूमिका,नियुक्ति की वैधता और अनुपस्थिति अवधि के वेतन भुगतान की जांच कौन करेगा?
- अनिल कुमार बनज का संरक्षण या विवेक चौरसिया पर विशेष मेहरबानी? गलती पर गलती,फिर भी नियुक्ति और लाखों का भुगतान!
- नियुक्ति का आदेश नहीं,फिर भी नौकरी पक्की! विवेक चौरसिया के लिए बदलती रही कार्यवाही पंजी?
- कभी हटाया,कभी बहाल किया,फिर लाखों का भुगतान! विवेक चौरसिया के मामले में सहकारिता के नियम किसके इशारे पर चले?
- अनिल कुमार बनज के रहते विवेक चौरसिया की हर राह आसान? नियुक्ति से भुगतान तक उठे गंभीर सवाल
- समिति में नियुक्ति का आदेश नहीं,हाईकोर्ट से राहत नहीं,फिर भी कुर्सी बरकरार! सहकारिता के फैसलों पर सवाल
- हटाने के आदेश से बहाली तक का रहस्यमय सफर! विवेक चौरसिया के मामले में सहकारिता विभाग की भूमिका कठघरे में
- सहकारिता में नियम-कानून या 'विशेष कृपा' का राज? विवेक चौरसिया की नियुक्ति और भुगतान पर घमासान
- वर्ष 2023 में वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर हुई अस्थायी नियुक्ति, नियुक्ति आदेश का पता नहीं 2025 में सेवा से पृथक, 2026 में पुराने निर्देशों के सहारे वापसी!
- 7 अगस्त और 5 सितंबर को नए कार्यवाही पंजी संधारित कर निर्णय लेने के आरोप,अनुपस्थिति अवधि के लाखों रुपये भुगतान पर भी सवाल





-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,23 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सहकारिता विभाग में नियम-कायदे आखिर किसके लिए बनाए गए हैं? समिति के सामान्य कर्मचारियों के लिए,बेरोजगार युवाओं के लिए या फिर उन चुनिंदा लोगों के लिए जिनके मामले में हर विवाद का कोई न कोई रास्ता निकल आता है? सोनपुर समिति से जुड़ा विवेक कुमार चौरसिया का मामला इन सवालों को और गंभीर बना रहा है,यहां नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठे,नियुक्ति आदेश की उपलब्धता पर सवाल उठे, सेवा से पृथक किए जाने के बाद दोबारा काम पर रखने पर सवाल उठे और अब कार्य पर उपस्थित नहीं रहने की अवधि के लाखों रुपये वेतन भुगतान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सहकारिता विभाग के प्रभारी उप पंजीयक अनिल कुमार बनज की भूमिका पर भी शिकायतकर्ताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं,आरोप है कि विवेक कुमार चौरसिया के मामले में विभागीय स्तर पर ऐसी नरमी दिखाई गई कि एक के बाद एक विवाद सामने आने के बावजूद उन्हें राहत मिलने का रास्ता निकलता रहा,हालांकि संरक्षण या मिलीभगत के आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है,लेकिन घटनाक्रम में सामने आए दस्तावेजी सवालों का जवाब देना विभाग की जिम्मेदारी है,मामला केवल एक कर्मचारी को काम पर रखने या हटाने का नहीं है,सवाल यह है कि क्या समिति की नियुक्ति प्रक्रिया, बोर्ड के प्रस्ताव, बैठक की सूचना,कार्यवाही पंजी और वेतन भुगतान के नियम किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग-अलग हो सकते हैं? क्या एक बार नियुक्ति पर सवाल उठ जाएं तो पुराने आदेशों का हवाला देकर नई राह बनाई जा सकती है? और क्या कार्य पर उपस्थित नहीं रहने की अवधि का वेतन भी बैठक में प्रस्ताव पारित कर भुगतान किया जा सकता है? अगर यह सब नियमों के अनुरूप हुआ है तो संबंधित अधिकारी दस्तावेजों के साथ स्थिति स्पष्ट करें। लेकिन यदि प्रक्रिया में अनियमितता हुई है तो जिम्मेदारी तय करने से आखिर परहेज क्यों?

2023 में अस्थायी व्यवस्था,लेकिन नियुक्ति आदेश कहां?-उपलब्ध घटनाक्रम के अनुसार, विवेक कुमार चौरसिया को वर्ष 2023 में समिति के बोर्ड द्वारा प्रस्ताव एवं ठहराव पारित कर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी लिपिक के रूप में कार्य में रखा गया था,बताया गया है कि उनके पक्ष में कोई विधिवत नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया, यहीं से पूरे प्रकरण का पहला सवाल शुरू होता है,जब नियुक्ति अस्थायी और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत थी तो उसकी शर्तें क्या थीं? नियुक्ति की अवधि कितनी थी? क्या किसी पद के विरुद्ध नियुक्ति की गई थी? क्या चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी? और सबसे महत्वपूर्ण, यदि नियुक्ति आदेश ही जारी नहीं हुआ था तो बाद में सेवा से पृथक करने और पुनः कार्य पर रखने की प्रक्रिया किस आधार पर संचालित हुई? सहकारिता व्यवस्था में शायद नियुक्ति आदेश से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्ताव और ठहराव हो गया है! लेकिन प्रस्ताव की भी अपनी मर्यादा और वैधानिक प्रक्रिया होती है,सवाल यह है कि क्या इस मामले में उन सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया?

10 जुलाई 2025 को सेवा से पृथक,फिर शिकायतों का सिलसिला

घटनाक्रम के अनुसार,10 जुलाई 2025 से विवेक कुमार चौरसिया को संस्था और संस्था के समस्त कार्यों से पृथक कर दिया गया,इस निर्णय के विरुद्ध उन्होंने महामहिम राज्यपाल और कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की,इसके बाद उपायुक्त सहकारिता,जिला सूरजपुर ने समिति से नियुक्ति संबंधी दस्तावेज और समिति का जवाब प्राप्त किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार,2 जनवरी 2026 को निर्णय देते हुए यह कहा गया कि यदि विवेक चौरसिया को बोर्ड का निर्णय मान्य नहीं है तो वे सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं,अर्थात मामला सक्षम न्यायालय में ले जाने का रास्ता बताया गया,लेकिन इसके बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया,विवेक चौरसिया ने संयुक्त आयुक्त सरगुजा संभाग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर दी।

27 जनवरी का निर्देश और संस्था के जवाब के बाद खामोशी-विवेक चौरसिया की शिकायत पर संयुक्त आयुक्त सरगुजा संभाग द्वारा 27 जनवरी 2026 को उन्हें कार्य में रखे जाने के संबंध में निर्देश जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है,संस्था का कहना है कि इस निर्देश के विरुद्ध उसने अपना पक्ष और तथ्य प्रस्तुत किए,लेकिन संस्था द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद आगे कोई स्पष्ट आदेश या निर्देश जारी नहीं किया गया,अब सवाल यह है कि यदि संस्था ने अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत किए थे तो उनका परीक्षण किस स्तर पर हुआ? क्या संयुक्त आयुक्त कार्यालय ने उन दस्तावेजों पर कोई अंतिम निर्णय दिया? क्या निर्देश को संशोधित किया गया या उसे यथावत रखा गया? और यदि कोई अंतिम आदेश नहीं था तो बाद में समिति में विवेक चौरसिया को दोबारा कार्य पर रखने का आधार क्या बना? यहां प्रशासनिक प्रक्रिया का एक विचित्र पहलू सामने आता है-शिकायत पर निर्देश जारी हुआ,संस्था ने जवाब दिया, फिर आगे की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई,लेकिन नियुक्ति की गाड़ी फिर भी आगे बढ़ती दिखाई देती है। आखिर किस आदेश के पहियों पर?

उच्च न्यायालय पहुंचे विवेक चौरसिया,याचिका खारिज होने के बाद भी सवाल कायम-इस विवाद में विवेक कुमार चौरसिया द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर का भी दरवाजा खटखटाया गया,उपलब्ध जानकारी के अनुसार,उच्च न्यायालय ने प्रकरण को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया, यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि याचिका खारिज होने का अर्थ अपने आप में नियुक्ति संबंधी प्रत्येक आरोप का न्यायिक परीक्षण या दोषमुक्ति नहीं माना जा सकता,इसके लिए न्यायालय के वास्तविक आदेश और उसमें दर्ज कारणों को देखना आवश्यक है,लेकिन सवाल फिर भी कायम है कि जब नियुक्ति और सेवा से पृथक किए जाने को लेकर विवाद न्यायिक स्तर तक पहुंच चुका था,तब समिति में दोबारा कार्य पर रखने से पहले सभी पुराने दस्तावेजों और आदेशों का परीक्षण क्यों नहीं किया गया?

प्राधिकृत अधिकारी बदले,व्यवस्था बदली और 7 अगस्त को नया कार्यवाही पंजी!-अब इस प्रकरण का सबसे दिलचस्प और गंभीर अध्याय शुरू होता है,घटनाक्रम के अनुसार, समिति के प्राधिकृत अधिकारी दुर्गाचरण सिंह के विरुद्ध शिकायत की गई और बाद में उन्हें अयोग्य बताते हुए पद से हटाया गया,इसके बाद समिति के प्राधिकृत अधिकारी का दायित्व शाखा प्रबंधक भैयाथान को सौंपा गया, 6 अगस्त 2026 को शाखा प्रबंधक भैयाथान सह प्राधिकृत अधिकारी सोनपुर द्वारा 7 अगस्त को बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए सूचना जारी की गई,आरोप है कि बैठक की सूचना में बैठक का स्पष्ट एजेंडा और विषय उल्लेखित नहीं था,फिर 7 अगस्त को क्या हुआ? शिकायतकर्ताओं के अनुसार, सचिव की अनुपस्थिति में एक नया बैठक कार्यवाही पंजी संधारित किया गया,एक दिन के लिए कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया और पुराने निर्देशों का हवाला देते हुए विवेक कुमार चौरसिया को दोबारा कार्य में रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया,अब यहां कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब केवल एक लाइन में नहीं दिया जा सकता,बैठक की सूचना में स्पष्ट एजेंडा क्यों नहीं था? क्या सभी पात्र बोर्ड सदस्यों को नियमानुसार सूचना दी गई थी? सचिव की अनुपस्थिति में एक दिन के लिए कार्यवाहक सचिव नियुक्त करने का आधार क्या था? क्या नए कार्यवाही पंजी का विधिवत संधारण और प्रमाणीकरण किया गया? क्या विवेक चौरसिया को पहले कार्य में रखने और फिर हटाने से संबंधित सभी पुराने दस्तावेजों का परीक्षण किया गया? क्या नियुक्ति आदेश की अनुपस्थिति और न्यायालयीन कार्यवाही को ध्यान में रखा गया? अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था तो पुराने अभिलेखों के आधार पर ही पारदर्शी तरीके से निर्णय क्यों नहीं लिया गया? नया कार्यवाही पंजी संधारित करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या समिति में अब निर्णय लेने के लिए पुराने रजिस्टर कम पड़ने लगे हैं या नए रजिस्टर में निर्णय ज्यादा सुविधाजनक हो जाते हैं?

5 सितंबर की बैठक:काम पर नहीं रहने की अवधि का वेतन भी मंजूर?-7 अगस्त की बैठक के बाद 5 सितंबर 2026 का घटनाक्रम और भी गंभीर सवाल खड़े करता है, आरोप है कि इस दिन बैठक के लिए बिना पूर्व सूचना जारी किए नया बैठक कार्यवाही पंजी संधारित किया गया,बैठक संचालन के लिए नया सचिव अथवा प्रबंधक नियुक्त किया गया और प्रस्ताव-ठहराव पारित कर विवेक कुमार चौरसिया को उस अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया, जिस दौरान वे कार्य पर उपस्थित नहीं थे,यही वह बिंदु है जहां मामला केवल नियुक्ति विवाद से आगे बढ़कर समिति के वित्तीय प्रबंधन और भुगतान प्रक्रिया तक पहुंच जाता है,यदि कर्मचारी संबंधित अवधि में कार्य पर उपस्थित नहीं था तो उस अवधि के वेतन भुगतान की पात्रता किस आधार पर तय की गई? क्या उस अवधि का कोई सेवा संबंधी आदेश था? क्या उपस्थिति पंजी में कार्य पर उपस्थित रहने का रिकॉर्ड था? क्या भुगतान से पहले सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गई? क्या उच्च कार्यालय को इसकी जानकारी दी गई? क्या वेतन भुगतान की गणना और पात्रता का परीक्षण हुआ? और यदि भुगतान लंबित वेतन के रूप में किया गया तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि लंबित वेतन किस आदेश के आधार पर देय था,समिति के खजाने से भुगतान करना कोई सामान्य प्रस्ताव पारित करने जैसा विषय नहीं है, यह सार्वजनिक और संस्थागत धन से जुड़ा मामला है,इसलिए भुगतान की प्रत्येक राशि के पीछे वैधानिक आधार,स्वीकृति और अभिलेख होना जरूरी है, यहां व्यंग्यात्मक सवाल भी उठता है-कर्मचारी काम पर रहे या नहीं,वेतन का रास्ता बैठक से निकल सकता है? अगर ऐसा है तो समिति के दूसरे कर्मचारियों को भी यह सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? या फिर यह सुविधा केवल चुनिंदा मामलों के लिए सुरक्षित है?

30 सितंबर की आमसभा में विरोध, सदस्यों को जवाब कौन देगा?-30 सितंबर 2026 को समिति की वार्षिक आमसभा में विवेक कुमार चौरसिया की नियुक्ति को लेकर आपत्ति उठाए जाने की जानकारी सामने आई है, आरोप है कि बैठक में प्राधिकृत अधिकारी अनुपस्थित रहे और सदस्यों ने नियुक्ति तथा वेतन भुगतान से संबंधित निर्णयों पर सवाल उठाए,सदस्यों की ओर से यह आपत्ति सामने आई कि बैठक कार्यवाही पंजी बार-बार बदलकर नियुक्ति और भुगतान से जुड़े प्रस्ताव क्यों पारित किए गए? उन्हें पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी गई? यदि समिति के सदस्य ही यह नहीं समझ पा रहे कि नियुक्ति किस आधार पर हुई,सेवा से पृथक करने का आदेश क्या था और अनुपस्थिति अवधि का भुगतान किस नियम से किया गया,तो फिर पारदर्शिता का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? समिति किसी एक व्यक्ति की निजी व्यवस्था नहीं है,इसके निर्णयों में सदस्यों का विश्वास और नियमों का पालन जरूरी है, आमसभा में उठी आपत्तियों का लिखित जवाब देना और मूल अभिलेखों को उपलब्ध कराना समिति प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

बेरोजगार युवाओं की शिकायत और 12 अक्टूबर को फिर पृथक्करण-विवेक कुमार चौरसिया की नियुक्ति को लेकर समिति कार्यक्षेत्र के बेरोजगार युवाओं द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत किए जाने की जानकारी दी गई है,इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए समिति के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को विवेक चौरसिया को समिति और समिति के समस्त कार्यों से पृथक करने का आदेश जारी किया गया,यानी जिस कर्मचारी को अगस्त में दोबारा कार्य पर रखने की प्रक्रिया अपनाई गई, उसी कर्मचारी को अक्टूबर में फिर से पृथक कर दिया गया। अब सवाल यह है कि अगस्त में कार्य पर रखने का निर्णय किन दस्तावेजों के आधार पर लिया गया था और अक्टूबर में पृथक करने का आधार क्या बना? क्या अगस्त में सभी तथ्य सही थे और अक्टूबर में नए तथ्य सामने आए? या फिर अगस्त में ही पुराने आदेशों और नियुक्ति की स्थिति का पूरा परीक्षण नहीं किया गया था? दोनों स्थितियों में जवाबदेही तय होनी चाहिए।

सहकारिता न्यायालय का स्थगन : आदेश का आधार और दायरा सार्वजनिक हो-12 अक्टूबर के आदेश के विरुद्ध विवेक कुमार चौरसिया द्वारा सहकारिता न्यायालय की शरण लेने की जानकारी है,बताया जा रहा है कि न्यायालय से उनके पक्ष में स्थगन आदेश पारित हुआ है,लेकिन इस आदेश को लेकर भी स्पष्टता जरूरी है। क्या न्यायालय के समक्ष नियुक्ति से संबंधित सभी पुराने दस्तावेज,7 अगस्त और 5 सितंबर की बैठक कार्यवाही,भुगतान अभिलेख तथा 12 अक्टूबर का आदेश प्रस्तुत किए गए थे? स्थगन आदेश किन तथ्यों और आधारों पर दिया गया? उसका दायरा क्या है? क्या यह केवल पृथक्करण आदेश पर रोक है या अन्य विषयों को भी प्रभावित करता है? स्थगन आदेश अंतिम निर्णय नहीं होता। इसलिए न्यायालयीन आदेश की वास्तविक भाषा और प्रभाव को सामने रखे बिना किसी पक्ष को पूरी तरह सही या गलत ठहराना उचित नहीं होगा।

अनिल कुमार बनज से सवाल : आखिर इस पूरे मामले की जवाबदेही किसकी?-पूरे घटनाक्रम में प्रभारी उप पंजीयक अनिल कुमार बनज की भूमिका पर उठ रहे सवालों का जवाब सामने आना जरूरी है,शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि विवेक चौरसिया के मामले में विभागीय संरक्षण के कारण उन्हें बार-बार राहत मिलती रही,लेकिन विभागीय स्तर पर इस आरोप का जवाब केवल मौन रहकर नहीं दिया जा सकता,अनिल कुमार बनज से यह स्पष्ट होना चाहिए कि वर्ष 2023 की अस्थायी नियुक्ति की वैधानिक स्थिति क्या है? क्या विवेक चौरसिया के पक्ष में कोई विधिवत नियुक्ति आदेश जारी हुआ था? 27 जनवरी 2026 के निर्देश के बाद संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किस स्तर पर किया गया? 7 अगस्त की बैठक में नया कार्यवाही पंजी संधारित करने और एक दिन के लिए कार्यवाहक सचिव नियुक्त करने की प्रक्रिया नियमसम्मत थी या नहीं? 5 सितंबर को अनुपस्थिति अवधि के वेतन भुगतान की स्वीकृति किस आधार पर दी गई? क्या भुगतान से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई थी? 30 सितंबर की आमसभा में सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर क्या कार्रवाई हुई? 12 अक्टूबर को दोबारा पृथक किए जाने के बाद विभाग ने नियुक्ति विवाद की निष्पक्ष जांच कराई या नहीं? यदि विभाग का मानना है कि सभी निर्णय नियमानुसार हुए हैं तो उसे दस्तावेजों के साथ यह साबित करना चाहिए, और यदि प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

मामला एक कर्मचारी का नहीं, सहकारिता व्यवस्था की विश्वसनीयता का है-इस पूरे विवाद को केवल विवेक कुमार चौरसिया बनाम समिति के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा, यह मामला समिति के अभिलेखों की विश्वसनीयता,नियुक्ति प्रक्रिया,बोर्ड के अधिकार, वित्तीय भुगतान और सहकारिता विभाग की निगरानी व्यवस्था की परीक्षा है, आज सवाल यह नहीं है कि विवेक चौरसिया को काम पर रखा जाए या हटाया जाए, सवाल यह है कि जो भी निर्णय लिया जाए,वह नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लिया जाए,अगर नियुक्ति वैध है तो उसका आदेश दिखाया जाए,यदि वेतन भुगतान सही है तो भुगतान का आधार और स्वीकृति सामने लाई जाए,यदि बैठकें नियमसम्मत थीं तो उनके मूल रजिस्टर और सूचना की प्रक्रिया जांच के लिए उपलब्ध कराई जाए,आखिर यह कैसी व्यवस्था है जहां नियुक्ति पर विवाद हो,फिर सेवा से पृथक किया जाए, फिर पुराने निर्देशों का हवाला देकर वापसी हो, फिर अनुपस्थिति अवधि का वेतन भुगतान हो और फिर दोबारा पृथक करने का आदेश जारी हो जाए? क्या सहकारिता विभाग में नियमों का पालन जरूरी है या नियमों की व्याख्या इस बात पर निर्भर करती है कि मामला किसका है? क्या समिति के मूल अभिलेखों से ज्यादा ताकत नए कार्यवाही पंजी में दर्ज प्रस्तावों की हो गई है? अब जरूरत है कि जिला और संभाग स्तर से अलग, निष्पक्ष एवं दस्तावेज आधारित जांच कराई जाए, वर्ष 2023 से अब तक के सभी आदेश, बैठक रजिस्टर,उपस्थिति पंजी,वेतन भुगतान अभिलेख और न्यायालयीन आदेशों का परीक्षण हो,जांच में यह भी तय हो कि किस अधिकारी ने कौन-सा निर्णय किस अधिकार से लिया और उससे समिति को वित्तीय अथवा प्रशासनिक नुकसान हुआ या नहीं,क्योंकि यदि हर विवाद का समाधान नया रजिस्टर खोलकर और हर आपत्ति का जवाब नया प्रस्ताव पारित करके दिया जाने लगे,तो फिर नियमावली की जरूरत ही क्या रह जाएगी?

CMYK



दंतैल का तांडव! सोनहत-रामगढ़ जंगल मार्ग पर व्यापारियों से भरे माजदा पर हमला,भागकर बचाई जान

दहशत में सोनहत-रामगढ़ मार्ग,दंतैल ने माजदा वाहन को बनाया निशाना...बाल-बाल बचे 10 से 15 व्यापारी

जंगल मार्ग पर मौत बनकर आया दंतैल,हाथी के हमले से गड्ढे में उतरा व्यापारियों का वाहन

हाथी के हमले से मचा हड़कंप,टूटे शीशे और क्षतिग्रस्त वाहन छोड़ जान बचाकर भागे व्यापारी

टाइगर रिजर्व के जंगल में दंतैल का हमला,व्यापारियों से भरा माजदा क्षतिग्रस्त,बड़ी अनहोनी टली

गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के सोनहत-रामगढ़ मार्ग पर अचानक सामने आया दंतैल

वाहन का अगला शीशा टूटा,झाड़ियों के बीच गड्ढे में फंसा माजदा,वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल

-रवि सिंह-

सोनहत (कोरिया),23 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जंगल के बीच से गुजरती सड़क पर सफर कर रहे व्यापारियों के लिए कुछ पल ऐसे भयावह बन गए कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वाहन छोड़कर भागना पड़ा,गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के घने जंगल से गुजरने वाले सोनहत-रामगढ़ मार्ग पर एक दंतैल हाथी ने व्यापारियों से भरे माजदा वाहन पर अचानक हमला कर दिया,हाथी के अप्रत्याशित हमले से वाहन में सवार लोगों के बीच चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई। चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और सफेद रंग का माजदा सड़क से नीचे उतरकर झाड़ियों के बीच गड्ढे में जा फंसा,हमले में वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और सामने का शीशा टूट गया, वाहन में सवार लगभग 10 से 15 व्यापारियों ने किसी तरह बाहर निकलकर हाथी से दूर सुरक्षित दिशा में भागते हुए अपनी जान बचाई, गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है,कुछ क्षणों की देरी या जरा-सी चूक भी बड़ी जनहानि में बदल सकती थी,यह घटना केवल एक वाहन पर हाथी के हमले की कहानी नहीं है,बल्कि जंगल मार्गों से गुजरने वाले ग्रामीणों,व्यापारियों और आम राहगीरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है,जिस रास्ते से लोग रोजमर्रा के कामकाज और व्यापार के सिलसिले में आवाजाही करते हैं,वहां अचानक दंतैल का सामने आ जाना और वाहन पर हमला कर देना बताता है कि वन्यजीवों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में यात्रा कितनी जोखिम भरी हो सकती है।

सोनहत से रामगढ़ जा रहे थे व्यापारी, जंगल में अचानक सामने आया दंतैल

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनहत क्षेत्र के लगभग 10 से 15 व्यापारी एक सफेद रंग के माजदा वाहन में सवार होकर रामगढ़ की ओर जा रहे थे,उनका वाहन गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के जंगल क्षेत्र से होकर गुजरने वाली पक्की सड़क पर आगे बढ़ रहा था, इसी दौरान जंगल की ओर से अचानक एक विशालकाय दंतैल हाथी सड़क पर आ पहुंचा, वाहन में बैठे लोगों को संभलने और स्थिति को समझने का पर्याप्त मौका भी नहीं मिल पाया, हाथी का अचानक सामने आना और फिर वाहन की ओर आक्रामक ढंग से बढ़ना यात्रियों के लिए दहशत भरा अनुभव बन गया,जंगल के बीच सीमित रास्ते और आसपास घनी झाड़ियों के कारण ऐसी परिस्थिति में वाहन चालक के सामने सुरक्षित रास्ता चुनना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है,इस घटना में भी हाथी के हमले के दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया और देखते ही देखते सामान्य सफर जान बचाने की जद्दोजहद में बदल गया।

हमला होते ही बेकाबू हुआ वाहन,गड्ढे में जा फंसा माजदा-प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी के हमले के दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका,माजदा ट्रक सड़क से नीचे उतरकर किनारे की झाड़ियों और गड्ढे की तरफ तिरछा होकर फंस गया। हाथी के हमले से वाहन के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ और अगला शीशा टूट गया, वाहन की यह स्थिति देखकर उसमें सवार व्यापारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी जान बचाने की थी,बताया जा रहा है कि सभी व्यापारी तत्काल वाहन से बाहर निकले और हाथी से दूरी बनाते हुए सुरक्षित दिशा की ओर भागे,मौके पर कुछ देर तक भय और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा,वाहन के क्षतिग्रस्त होने और उसके सड़क किनारे गड्ढे में उतर जाने से घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है,यदि व्यापारी समय रहते वाहन से बाहर नहीं निकलते या हाथी की चपेट में आ जाते,तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकते थे।

वायरल वीडियो में कैद हुई दहशत, जान बचाने के लिए भागते दिखे व्यापारी

घटना का वीडियो भी सामने आया है,जिसमें हमले के बाद की स्थिति दिखाई दे रही है,वीडियो में सड़क पर पीछे की ओर दंतैल हाथी खड़ा नजर आता है, जबकि सफेद रंग का माजदा वाहन सड़क किनारे झाड़ियों की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है,वाहन में सवार लोग जान बचाने के लिए तेजी से सुरक्षित दिशा की ओर भागते नजर आ रहे हैं, वीडियो में दिखाई देने वाला दृश्य जंगल मार्ग पर अचानक हाथी के सामने आ जाने से पैदा होने वाले खतरे की गंभीरता को सामने लाता है,हालांकि हाथी ने वाहन पर किस तरह और कितनी बार हमला किया,इसकी विस्तृत जानकारी तथा घटना का पूरा क्रम संबंधित विभाग की जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से ही स्पष्ट हो सकेगा,फिलहाल वीडियो ने स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

सवालों के घेरे में जंगल मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था-सोनहत से रामगढ़ की ओर जाने वाला मार्ग वन क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस रास्ते से स्थानीय ग्रामीणों,व्यापारियों और अन्य राहगीरों का आवागमन होता है,ऐसे में हाथियों की आवाजाही वाले इस क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना वन विभाग और टाइगर रिजर्व प्रबंधन के सामने महत्वपूर्ण चुनौती है,हाथियों का जंगल से निकलकर सड़क पर आ जाना और वाहनों के सामने अचानक पहुंच जाना यात्रियों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है,विशेषकर जब वाहन में कई लोग सवार हों और आसपास घना जंगल हो, तब आपात स्थिति में सुरक्षित निकलने का विकल्प भी सीमित रह जाता है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या इस संवेदनशील मार्ग पर वन्यजीवों की गतिविधियों की पर्याप्त निगरानी की जा रही है? क्या हाथियों की मौजूदगी की सूचना समय रहते राहगीरों तक पहुंचाने की कोई प्रभावी व्यवस्था है?

चेतावनी बोर्ड,मुनादी और नियमित गश्त की जरूरत-घटना के बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने वन विभाग तथा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व प्रबंधन से सोनहत-रामगढ़ जंगल मार्ग पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है,लोगों का कहना है कि हाथियों के विचरण वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाए जाने चाहिए,वन अमले की नियमित गश्त के साथ जरूरत के अनुसार मुनादी और अन्य संचार माध्यमों से राहगीरों को हाथियों की मौजूदगी की जानकारी दी जानी चाहिए,इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने और मार्ग से गुजरने वाले लोगों को समय रहते सतर्क करने की व्यवस्था भी जरूरी है,यदि किसी क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलती है, तो संबंधित मार्ग पर आवाजाही करने वालों तक यह सूचना पहुंचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।

बड़ी अनहोनी टली,लेकिन अगली बार कौन होगा सुरक्षित?

दंतैल हाथी के हमले में व्यापारियों का सुरक्षित बच निकलना निश्चित रूप से राहत की बात है, लेकिन इस घटना को महज एक वाहन के क्षतिग्रस्त होने तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, वाहन में 10 से 15 लोग सवार थे, हाथी के हमले के बाद वाहन सड़क से नीचे उतर गया और सामने का शीशा टूट गया,यह घटनाक्रम बताता है कि जंगल मार्ग पर अचानक वन्यजीव के सामने आने की स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है,अब वन विभाग और टाइगर रिजर्व प्रबंधन के सामने यह जिम्मेदारी है कि घटना की परिस्थितियों का निरीक्षण करे, हाथियों की आवाजाही वाले संवेदनशील हिस्सों की पहचान करे और सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। व्यापारियों और स्थानीय राहगीरों की मांग है कि जंगल मार्ग पर निगरानी तथा चेतावनी की व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर दिखाई दे,फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वन विभाग किसी बड़ी जनहानि की प्रतीक्षा किए बिना सोनहत-रामगढ़ जंगल मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा? क्योंकि इस बार व्यापारियों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन अगली बार किसी वाहन चालक या राहगीर को इतना समय और अवसर मिल पाएगा,इसकी कोई गारंटी नहीं है।

मवेशी तस्करी के फरार आरोपी को रामचंद्रपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

पिकअप नाले में गिरने के बाद भाग निकला था तस्कर



-संवाददाता-

रामचंद्रपुर,23 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी ने एक पिकअप वाहन में मवेशियों को भरकर बूचड़खाने ले जा रहा था,लेकिन वाहन के नाले में गिर जाने के बाद वह मवेशियों को वहीं छोड़कर मौके से भाग निकला था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी बबन सिंह (निवासी ग्राम अनपारा, थाना रामचंद्रपुर) ने थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि एक पिकअप वाहन (क्रमांक JH03AW1695) से 07 नग मवेशियों को बूचड़खाना (झारखंड) की ओर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान पिकअप वाहन नाले में गिर गया, जिसके बाद तस्कर मवेशियों को वहीं छोड़कर फरार हो गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की तस्दीक की और थाना रामचंद्रपुर में अपराध क्रमांक 53/2026 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 04, 06, 10 तथा छत्तीसगढ़ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में 22 नवंबर 2026 को आरोपी साहू अंसारी (पिता शाकिर अंसारी, उम्र 29 वर्ष,निवासी ग्राम लेडी कांड,थाना रंका,जिला गढ़वा, झारखंड) को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।

मेडिकल बिलों में देरी पर डीईओ का आधिकारिक पत्र,डीडीओ की कार्यप्रणाली पर उठा सवाल

■ शालेय शिक्षक संघ की शिकायत के बीच जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी डीडीओ को जारी किए निर्देश

■ सिविल सर्जन से पारित चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक समय पर जिला कार्यालय में प्रस्तुत नहीं होने की बात पत्र में स्वीकार

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,23 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

बीमार शिक्षकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान में हो रही देरी को लेकर छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ द्वारा उठाया गया मुद्दा अब विभागीय पत्राचार में भी सामने आ गया है,जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर ने 23 नवंबर 2026 को जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को पत्र जारी कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय-सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं,डीईओ के इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संबंधित डीडीओ द्वारा सिविल सर्जन से पारित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी देयक समय पर जिला कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं,इसके कारण कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि की मांग उच्च कार्यालय को भेजने में विलंब हो रहा है और समय पर भुगतान के लिए बजट आवंटन एवं पुनर्बंटन में भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है,शालेय शिक्षक संघ पहले से ही आरोप लगाता रहा है कि शिक्षकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण महीनों तक लंबित रखे जा रहे हैं और बीमार कर्मचारियों को अपनी ही राशि प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, अब डीईओ के आधिकारिक पत्र में डीडीओ स्तर पर देयक समय पर प्रस्तुत नहीं होने की बात सामने आने के बाद इस मामले में विभागीय जवाबदेही का प्रश्न और महत्वपूर्ण हो गया है।

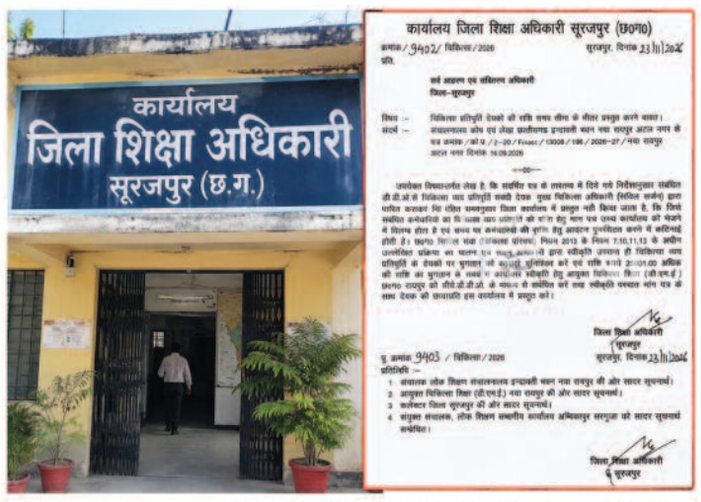

डीईओ के पत्र में देरी की वजह का उल्लेख,अब जवाबदेही किसकी?-जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र क्रमांक 9402/ चिकित्सा / 2026,दिनांक 23 नवंबर 2026 में संचालनालय कोष एवं लेखा छत्तीसगढ़, नया रायपुर के 16 सितंबर 2026 के पत्र का संदर्भ दिया गया है,इसमें कहा गया है कि संबंधित डीडीओ द्वारा सिविल सर्जन से पारित चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक निर्धारित समय में जिला कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं,इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए मांग पत्र उच्च कार्यालय को भेजने में विलंब होता है और भुगतान के लिए आवश्यक बजट आवंटन एवं पुनर्बंटन की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है,यह उल्लेख महत्वपूर्ण है,क्योंकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान में देरी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विभागीय पत्र ने कम से कम देयक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में हो रही देरी को आधिकारिक रूप से दर्ज किया है,हालांकि, पत्र में किसी अधिकारी या कर्मचारी पर रिश्वत अथवा कमीशन लेने की पुष्टि नहीं की गई है, ऐसे आरोपों की स्वतंत्र जांच आवश्यक होगी।

25,001 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए भी स्पष्ट प्रक्रिया-डीईओ ने अपने पत्र में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 7,10,11 एवं 13 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए हैं,पत्र के अनुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ही चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के देयकों पर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए,इसके साथ ही 25,001 रुपये से अधिक की राशि के भुगतान के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़,रायपुर को सीधे डीडीओ के माध्यम से प्रकरण प्रेषित करने को कहा गया है, स्वीकृति मिलने के बाद मांग पत्र के साथ संबंधित देयक की छायाप्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया गया है, इस निर्देश से स्पष्ट है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया और सक्षम स्तर की स्वीकृति जरूरी है, ऐसे में किसी भी स्तर पर देयक लंबित रखने या निर्धारित प्रक्रिया का समय पर पालन नहीं करने से कर्मचारियों को होने वाली परेशानी की जिम्मेदारी तय करना भी आवश्यक है।

संघ का सवाल...बीमार शिक्षकों को अब तक क्यों लगाने पड़े कार्यालयों के चक्कर?-छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के जिला सचिव गौतम शर्मा ने सवाल उठाया है कि जब विभागीय पत्र में ही डीडीओ स्तर से देयक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित होने की बात सामने आ गई है,तो अब तक लंबित प्रकरणों के लिए जवाबदेही किसकी तय हुई? उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी के इलाज में अपनी जमा पूंजी खर्च करने अथवा कर्ज लेने वाले शिक्षकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में विभाग को यह बताना चाहिए कि लंबित प्रकरणों के निराकरण में अब तक देरी क्यों हुई, संघ के जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे ने कहा कि बीमार शिक्षक को राहत देने के बजाय उसे फाइलों और कार्यालयों के चक्कर में उलझाना उचित नहीं है,चिकित्सा प्रतिपूर्ति किसी अधिकारी की कृपा नहीं,बल्कि नियमों के तहत पात्र कर्मचारी को मिलने वाला अधिकार है,उन्होंने मांग की कि सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण किया जाए और जिन स्तरों पर लापरवाही के कारण देरी हुई है,उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

केवल निर्देश नहीं,लंबित प्रकरणों का निराकरण भी जरूरी

शालेय शिक्षक संघ ने मांग की है कि जिले के सभी विकासखंडों में लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों की समीक्षा कराई जाए, प्रत्येक प्रकरण की स्थिति,देरी की अवधि और संबंधित स्तर पर हुई कार्रवाई का विवरण तैयार किया जाए,जिन मामलों में दस्तावेज या स्वीकृति की कमी है,उन्हें तत्काल पूरा कराने की व्यवस्था हो तथा पात्र शिक्षकों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए,संघ ने विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की है,संघ का कहना है कि उसकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं,बल्कि उस व्यवस्था के विरुद्ध है जिसमें इलाज कराने के बाद भी शिक्षक अपनी चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाता है, डीईओ का निर्देश जारी होने के बाद अब निगाहें उसके पालन पर हैं। क्या जिले के सभी डीडीओ लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों को समय पर प्रस्तुत करेंगे? क्या विकासखंडवार समीक्षा कर देरी के कारणों और जिम्मेदारों की पहचान होगी? और सबसे अहम, क्या गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों को उनकी पात्र चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि समय पर मिल पाएगी? इन सवालों का जवाब अब विभागीय कार्रवाई से ही सामने आएगा।

C M Y K

मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूं... ईशा सिंह के ब्रेकअप में नया ट्विस्ट



भाई रुद्राक्ष ने शेयर की चैट, खोल के रख दिया अविनाश मिश्रा का काला चिट्ठा

ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के ब्रेकअप की चर्चाओं के बीच भाई रुद्राक्ष ने कथित व्हाट्सऐप चैट शेयर की। इसमें अविनाश माफी मांगते दिखे,जिसके बाद विवाद और गहरा गया। बिग बॉस 18 के चर्चित कंटेस्टेंट ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के रिश्ते में आई कथित दरार अब एक नए विवाद में बदलती नजर आ रही है। दोनों के ब्रेकअप और धोखे की खबरों के बीच ईशा के भाई रुद्राक्ष सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर एक कथित व्हाट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस बातचीत में अविनाश मिश्रा अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। रुद्राक्ष के इस खुलासे के बाद दोनों एक्टर्स की निजी जिंदगी एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

ईशा के भाई ने शेयर किया चैट का स्क्रीनशॉट

रुद्राक्ष ने सोमवार 23 नवंबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अविनाश के साथ हुई कथित व्हाट्सऐप बातचीत का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। इसमें रुद्राक्ष की ओर से भेजे गए कई वॉयस नोट्स के बाद अविनाश के टेक्स्ट मैसेज नजर आ रहे हैं। इन संदेशों में अविनाश अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफी मांगते दिखाई देते हैं। कथित चैट में अविनाश ने लिखा,भाई,मैं जो कुछ भी किया है,उसका बचाव या उसे सही साबित नहीं कर सकता। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे खुद पर शर्म आ रही है और आप जो कुछ भी कह रहे हैं,मैं उससे सहमत हूं। मैंने जो किया है, उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं। इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए रुद्राक्ष ने अविनाश पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि 1 नवंबर को अविनाश खुद अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें कहानी को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए बेवफा गाने बजाने की हिम्मत कैसे हो रही है। उन्होंने आगे कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।

ईशा नहीं चाहतीं विवाद आगे बढ़े

रुद्राक्ष ने बाद में एक वीडियो मैसेज शेयर कर अपने परिवार का पक्ष भी रखा। उन्होंने बताया कि उनका परिवार किसी के खिलाफ नफरत फैलाना या विवाद को और बढ़ाना नहीं चाहता। ईशा भी इस पूरे मामले को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। वह इस स्थिति को समझदारी और परिपक्वता के साथ संभालना चाहती हैं। हालांकि रुद्राक्ष ने साफ किया कि वह अपनी बहन की चुप्पी को किसी के लिए कहानी बदलने का मौका नहीं बनने देना चाहते। उनके मुताबिक,उन्हें इस बात से परेशानी है कि बिना अपनी जिम्मेदारी स्वीकार किए कोई गाने बजाकर या सोशल मीडिया पर अलग संदेश देकर पूरे मामले का नैरेटिव बदलने की कोशिश करे। उन्होंने कहा,मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी शांति का फायदा उठाए और जिम्मेदारी लिए बिना गाने बजाकर कहानी को पलटने की कोशिश करे। इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। अब आप इसे असली मानते हैं या नहीं, यह मेरी और उसकी चैट है।

अविनाश ने बजाए थे बेवफा गाने

दरअसल कुछ दिन पहले अविनाश ने सोशल मीडिया पर बेवफा निकली है तू और दूरियां जैसे गाने बजाए थे। इसके बाद दोनों के रिश्ते में अनबन और ब्रेकअप की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईशा को अविनाश की कथित बेवफाई के बारे में पता चला,जिसके बाद उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। यह भी कहा गया कि ईशा ने इंस्टाग्राम पर अविनाश को अनफॉलो कर दिया और उनके साथ की तस्वीरें हटा दीं। हालांकि दोनों की ओर से ब्रेकअप पर आधिकारिक बयान नहीं साझा किया। बीते दिनों ईशा की मां का वॉइस नोट भी वायरल हुआ,जिसमें कहा गया कि ईशा के साथ अविनाश ने चीटिंग की है,इस मामले के चूल पकड़ने के बाद अविनाश मिश्रा ने पोस्ट साझा करते हुए कहा कि प्राइवेसी बनी रहने दी जाए और उनकी पर्सनल लाइफ को उछाला न जाए। बाद में ईशा का भी पोस्ट सामने आया जिसमें बिना नाम लिए उन्होंने भी आरोप लगाए।

बिग बॉस 18 में करीब आए थे ईशा और अविनाश

ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा की नजदीकियां बिग बॉस 18 के दौरान बढ़ी थीं। शो में उनकी दोस्ती को लेकर डेटिंग की अटकलें लगने लगी थीं। शो खत्म होने के बाद भी दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया। अविनाश के खतरों के खिलाड़ी 15 जीतने के बाद रखी गई पार्टी में भी दोनों का रिश्ता चर्चा में आया था। इस दौरान अविनाश ने ईशा के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा था,आई लव यू बेबी। ईशा ने भी जवाब में यही बात दोहराई थी। अब रुद्राक्ष के इस कथित चैट स्क्रीनशॉट ने उनके रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को फिर हवा दे दी है।



चाय की दीवानी हैं माधुरी दीक्षित, खोला घर का पुराना राज

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपनी शानदार अदाकारी, खूबसूरत मुस्कान और बेहतरीन डांस के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने वाली माधुरी ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी एक दिलचस्प बात साझा की है। अभिनेत्री ने क्विज शो कोण होणार करोड़पति में भुवन बाम के साथ बातचीत के दौरान चाय के प्रति अपने खास लगाव का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके घर में दिनभर चाय बनती रहती थी। माधुरी की इस बात ने उनके जीवन के एक ऐसे पहलू को सामने रखा,जो बेहद सामान्य होने के बावजूद कई लोगों के दिलों के करीब है। बॉलीवुड सितारों की जिंदगी को लेकर प्रशंसकों के मन में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। लोग अपने पसंदीदा कलाकारों की फिल्मों और पेशेवर उपलब्धियों के साथ-साथ उनकी रोजमर्रा की आदतों के बारे में भी जानना चाहते हैं। ऐसे में माधुरी दीक्षित का चाय को लेकर किया गया खुलासा चर्चा का विषय बन गया है। अभिनेत्री की बातों से यह पता चलता है कि चाय उनके घर की दिनचर्या का एक खास हिस्सा रही है।

भुवन बाम के साथ बातचीत में किया खुलासा

क्विज शो कोण होणार करोड़पति में माधुरी दीक्षित और भुवन बाम के बीच बातचीत के दौरान चाय का विषय सामने आया। इसी दौरान अभिनेत्री ने अपने घर में चाय बनाने की पुरानी आदत का जिक्र किया।माधुरी ने बताया कि उनके घर में दिनभर चाय बनती थी। उनका यह खुलासा भारतीय परिवारों की उस आम परंपरा की याद दिलाता है, जहां सुबह से लेकर शाम तक चाय का सिलसिला चलता रहता है।अभिनेत्री ने बातचीत के दौरान अपनी जिंदगी से जुड़ी इस छोटी लेकिन दिलचस्प बात को साझा किया। उनके इस अनुभव में घरेलू जीवन की सादगी की झलक देखने को मिलती है।भुवन बाम के साथ हुई इस बातचीत का मुख्य आकर्षण माधुरी का चाय के प्रति लगाव रहा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दोनों के बीच हुई पूरी बातचीत का विवरण सामने नहीं आया है।

घर में दिनभर चलता था चाय का दौर

भारत में चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं,बल्कि दैनिक जीवन और सामाजिक मेलजोल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुबह की शुरुआत हो या शाम को परिवार के साथ बैठने का समय,चाय अक्सर लोगों की दिनचर्या में शामिल रहती है।



2027 में शादी की चर्चा निकली अफवाह, सारा तेंदुलकर के रिश्ते पर आया बड़ा अपडेट

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की शादी को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही थीं। दावा किया जा रहा था कि दोनों साल 2027 में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि, अब इन खबरों पर विराम लगता नजर आ रहा है। सारा के करीबी एक सूत्र ने इन चर्चाओं को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा है कि सारा तेंदुलकर और राजवीर देओल कभी एक-दूसरे से मिले तक नहीं हैं। सारा के करीबी सूत्र ने स्पष्ट किया कि शादी की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। सूत्र ने बताया कि सारा फिलहाल सिंगल हैं और अपने काम पर ध्यान दे रही हैं। उनके और राजवीर के रिश्ते को लेकर फैलाई जा रही बातें अनावश्यक हैं। सूत्र ने यह भी कहा कि सारा इन अफवाहों पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं देना चाहतीं और गरिमापूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी जीना पसंद करती हैं। सोशल मीडिया पर हाल ही में ऐसी पोस्ट सामने आई थीं, जिनमें दावा किया गया था कि सारा तेंदुलकर और राजवीर देओल एक-दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों परिवार शादी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ पोस्ट में यह भी कहा गया था कि दोनों की शादी 2027 में हो सकती है। इन चर्चाओं के दौरान यह दावा भी किया गया कि राजवीर सारा को महंगे उपहार भेज रहे हैं।

खेल-समाचार

भारत यूएई के बीच मुकाबला आज

नई दिल्ली,23 नवम्बर 2026।

भारतीय टीम एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अब अगले मैच के लिए तैयारी कर रही है। जो भारतीय समय अनुसार सुबह साढ़े 11 बजे से शुरू हो जाएगा। भारत के लिए ये मैच अहम होगा।

एशिया कप राइजिंग स्टार्स में मुकाबले जारी है। भारत की ए टीम तिलक वर्मा की कप्तानी में अपना दूसरा मैच हार गई है। हालांकि पहला मैच टीम नेपाल से जीतने में कामयाब रही थी,इसलिए उसके पास दो अंक हैं और टीम सेमीफाइनल में जाने की रेस से बाहर नहीं हुई है। इस बीच भारतीय टीम अब अगले मैच के लिए तैयारी कर रही है,जो काफी अहम है,अगर इस मैच में हार मिली तो फिर इस टूर्नामेंट में सफर समाप्त भी हो सकता है।

भारत और यूएई के बीच 24 नवंबर को खेला जाएगा एशिया कप राइजिंग स्टार्स का मैच

भारत की ए टीम तिलक वर्मा की कप्तानी में एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अपना अगला मैच यूएई के खिलाफ खेलेगी। ये मैच 24 नवंबर यानी मंगलवार को खेला जाएगा। भारत ने 22 नवंबर को ही पाकिस्तान के खिलाफ खेला था,अब एक दिन के गैप के बाद फिर से मुकाबले की बारी है। ये मैच भी दोहा में ही खेला जाएगा। जहां तक मैच शुरू होने के वक्त की बात है तो ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह साढ़े 11 बजे से शुरू हो जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी 11 बजे टॉस होगा। इससे पहले भारत ने जो दो मैच खेले हैं, वो साढ़े तीन बजे शुरू हुए थे, लेकिन इस मैच की टाइमिंग अलग है।



पाकिस्तान,श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें सेमीफाइनल में पहुंचीं

अभी तक पाकिस्तान,श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें अपनी अपनी जगह सेमीफाइनल में बना चुकी हैं,अभी चौथी टीम का स्पॉट खाली है। उसके लिए टीम इंडिया की असली दावेदार हैं। 26 नवंबर से सेमी फाइनल मैच होने शुरू हो जाएंगे। 26 को पहला और उसके बाद 27 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। इन मैचों को जीतने वाली टीमें फाइनल में जाएंगी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल मैच 29 नवंबर यानी रविवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि अपना अगला मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचा जाए,इसके बाद फाइनल में भी अपनी जगह पक्की की जाए।

म्यूजियम में होगा बीजीएमआई का महासंग्राम,3 दिसंबर को 56 खिलाड़ी भिड़ेंगे

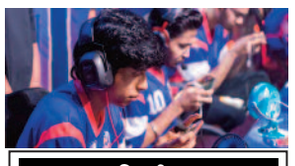

नई दिल्ली,23 नवम्बर 2026।

भारत के बेहतरीन सोलो बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खिलाड़ी 3 दिसंबर को देश के अगले सोलो लीजेंड का खिताब जीतने के लिए मुकाबला करेंगे। रेड बुल सोलो लीजेंड्स सीजन 2 का समापन गुरुग्राम के म्यूजियो कैमरा सेंटर फॉर द फोटोग्राफिक आर्ट्स में एक एलएएन फिनाले के साथ होगा। आम बीजीएमआई ई-स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं के विपरीत,जो चार खिलाड़ियों की टीमों पर आधारित होती हैं,रेड बुल सोलो लीजेंड्स में व्यक्तिगत कौशल को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसमें हर लड़ाई,मूवमेंट और सर्वाइवल से जुड़ा फैसला खिलाड़ी को खुद लेना होता है। इस तरह, यह बिना किसी टीम के साथियों के सपोर्ट के, खिलाड़ी की गेमिंग तकनीक,रणनीति और संयम की एक कड़ी परीक्षा बन जाती है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं नंदनी चौधरी पिता राम अवतार चौधरी आयु 21 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 20, हनुमान मंदिर, डी.सी. रोड, महावीरपारा, अम्बिकापुर, तह-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0)। यह कि मेरे आधार कार्ड क्र. 35025134 7947 में मेरा नाम नंदनी कुमारी (NANDANI KUMARI) त्रुटिवश अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरे कक्षा 10वीं के अंकसूची पंजीयन क्र. 19/751005/036 व रोल नं. 1217500798 है, जिसमें मेरा नाम नंदनी चौधरी (NANDANI CHOUDHARY) अंकित है, जो कि सही एवं सत्य है । मेरे आधार कार्ड में नाम नंदनी कुमारी (NANDANI KUMARI) से सुधार कर कक्षा 10वीं के आधार पर मेरा वास्तविक एवं सही नाम नंदनी चौधरी (NANDANI CHOUDHARY) अंकित किया जाना अति आवश्यक है। आधार कार्ड में सरनेम सुधार कराने के संबंध मैं स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

सपथकर्ता
नंदनी चौधरी

नाम परिवर्तन सूचना

(प्रारूप-एक)

मैं सुखदेव पिता शिवप्रसाद उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम कर्रा, थाना व तहसील धौरपुर जिला सरगुजा (छ.ग.) ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का इन्द्रावती सिंह (INDRAWAT SINGH) से बदल कर इन्द्रमुनी (INDRAMUNI) रख लिया है।

सुखदेव
माता/पिता/ पालक के हस्ताक्षर
संजय कुमार पाण्डेय

नाम परिवर्तन सूचना

(प्रारूप-एक)

मैं अनुरंजन कुमार खेस्स (ANURANJAN KUMAR KHESS) (पुराना नाम,जिसे बदला जाना है) सुपुत्र बिफन खेस्स गांव पोड़िपा, स्कूलपारा,पड़िया,सखोली तहसील दरिमा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ ने अपना नाम अनुरंजन कुमार खेस्स (ANURANJAN KUMAR KHESS) (पुराना नाम) से बदल कर, अनुरंजन खेस (ANURANJAN XESS) (नया नाम) रख लिया है।

शपथग्रहिता
अनुरंजन

छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
सरगुजा वनमण्डल,अम्बिकापुर (छ.ग.)

नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, कि सरगुजा वनमण्डल, के अधीनस्थ काष्ठागार अम्बिकापुर में भण्डारित ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का दर्शित तिथि एवं समय में ई-ऑक्शन किया जावेगा। इच्छुक व्यापारियों एवं अन्य क्रेताओं से अनुरोध है कि वे ई-ऑक्शन में भाग लेवें ई-ऑक्शन से संबंधित शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय / काष्ठागार अम्बिकापुर से प्राप्त की जा सकती है।

काष्ठागार अम्बिकापुर

नीलाम दिनांक- 25.11.2026 समय - प्रातः 09.00 बजे से

प्रजाति	नया वनोपज		पुराना वनोपज		योग वनोपज	
	लट्ठा (घ.मी.)	बल्ली (नग)	लट्ठा (घ.मी.)	बल्ली (नग)	लट्ठा (घ.मी.)	बल्ली (नग)
सागौन	26.416	380	71.868	1909	98.284	2289
साल	1096.023	984	5529.696	2090	6625.719	3074
बीजा	0.660	0	0.000	0	0.660	0
साजा	21.691	0	30.830	25	52.521	25
तिंसा	0.000	0	0.719	0	0.719	0
धावड़ा	7.160	0	17.116	0	24.276	0
सालिहा	9.950	0	46.089	6	56.039	6
हल्दू	1.229	0	16.672	0	17.901	0
नीलगिरी	2.219	0	0.000	0	2.219	0
खम्हार	0.000	0	54.990	2327	54.990	2327
अन्य	270.330	357	947.040	1654	1217.370	2011
बांसा	0.000	0	1.997	0	1.997	0
योगः—	1435.678	1721	6717.017	8011	8152.695	9732
जलाऊ	468	0	144	Chatta	612	Chatta

टीप -1. क्रेताओं को ई-ऑक्शन से पूर्व एम. एस. टी. सी. ई-कॉमर्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. क्रेताओं को ई-ऑक्शन के पूर्व क्रय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वालेट में रखना अनिवार्य है। सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई. एम. डी. की राशि जमा करना अनिवार्य है ।
3. लॉट की थप्पी सूची एवं फोटो एम. एस. टी. सी. ई-कॉमर्स पोर्टल में अपने आई.डी. से लॉग इन करके देख सकते हैं ।
4. ई-ऑक्शन में लॉट क्रय के पश्चात् प्रथम क्रेता को 30 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा, उसी लॉट में अन्य क्रेताओं द्वारा 20 सेकण्ड के पूर्व क्रय करने पर 20 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा ।

वनमंडलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

जी.नं.-262704636/2

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका सरदार सुरेन्द्र सिंह भामरा आ0 / पति स्व. सरदार उधम सिंह जाति, निवासी मायापुर,अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर,जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-मायापुर, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1598/18 रकबा 0.08 1/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 04.12.26 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 19.11.26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका सीताराम अग्रवाल आ0/ पति स्व. श्यामसुन्दर अग्रवाल जाति, निवासी महामाया रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-सत्तीपारा, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 830/6 रकबा 0.04 3/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 02.12.26 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 17.11.26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण फातमा बेगम पत्नि स्व.मो. इरफान अंसारी, उम्र- 52 वर्ष व अन्य 03 सभी निवासी मोहल्ला जरहागढ़, था0तह0 अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा के द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया है, कि नगर अम्बिकापुर,मोहल्ला-जरहागढ़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नं. 2341/5 रकबा 0.01 1/4 एकड़ भूमि भूधारक इरफान अंसारी के नाम पर दर्ज है। भूधारक इरफान अंसारी की मृत्यु दिनांक 15.05.2025 को हो गई है। तद्उपरांत उक्त भूमि से मृत्तक खातेदार मो0 इरफान अंसारी का नाम विलोपित कर फौति नामांतरण किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा आवेदित भूमि के मेंटनेंस खसरा एवं मृत्तक खातेदार के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 09/12/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक- 23/11/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील — **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक /आवेदिका रामजीत आ0/पति रामसुन्दर बारी जाति,निवासी नेहरू वार्ड सत्तीपारा अम्बिकापुर,तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला सत्तीपारा,शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 621/50, 622/4 रकबा 0.07 3/4, 0.06 1/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 30.11.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक- 22.10.26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर , जिला-सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क0 - /अ-27 / 2026 27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोतीलाल पिता जगमोहन उरांव व अन्य, निवासी महामाया पारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 2244/1, 2245/1 रकबा क्रमशः 0.017, 0.075 हे. भूमि को उभयपक्ष के मध्य में बटवारा किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 16/12/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक : 15/ 10/ 2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — **तहसीलदार अंबिकापुर जिला-सरगुजा(छ.ग.)**

मुख्यमंत्री साय ने धनोरा में दी 132.69 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

बिहान की दीदियां संभालेंगी धान के प्रसंस्करण से लेकर विपणन तक की जिम्मेदारी,ग्रामीण महिलाओं को मिलेंगे स्वरोजगार के नए अवसर : सीएम साय

- मुख्यमंत्री ने 2.50 करोड़ की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया लोकार्पण,56 गांवों के 56 हजार ग्रामीणों को मिलेगा लाभ
- 'कोंडानार प्रीमियम राइस' का किया शुभारंभ,730 किसानों की परंपरागत उपज को मिलेगी नई बाजार पहचान
- 84 गांवों की आस्था के केंद्र पेन खण्डा मुदिया के दर्शन कर मुख्यमंत्री ने की प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना
- आदिवासी समाज ने पारंपरिक साफा बांधकर किया मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत



रायपुर,23 नवम्बर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोण्डागांव जिले के ग्राम धनोरा में विकास कार्यों की सौगात देने के साथ ही किसानों की समृद्धि,महिलाओं की आत्मनिर्भरता और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने जिले में 132 करोड़ 69 लाख 43 हजार रुपये की लागत के 49 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया तथा सुदूर वनांचल के किसानों की उपज को नई बाजार पहचान दिलाने के लिए 'कोंडानार प्रीमियम राइस' ब्रांड का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कोनगुड़ परगना के प्रमुख आराध्य पेन खण्डा मुदिया के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे गांवों और वहां रहने वाले प्रत्येक परिवार तक पहुंचे। दूरस्थ वनांचलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही किसानों की मेहनत को उचित मूल्य और ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के नए अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों, परंपरागत कृषि पद्धतियों और ग्रामीण प्रतिभाओं को नए अवसरों से जोड़कर ही समृद्ध और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर 'कोंडानार प्रीमियम राइस' ब्रांड का शुभारंभ कर वनांचल के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की नई पहल की। इस ब्रांड के माध्यम से ग्राम बेचा, किलम,कड़ेनार और मंदोड़ा के लगभग 730 किसानों द्वारा परंपरागत तरीके से उत्पादित धान को संगठित बाजार से जोड़ा जाएगा।

इन गांवों के किसान लंबे समय से बिना रासायनिक खाद के प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक कृषि पद्धतियों के आधार पर धान की खेती करते आ रहे हैं। उनकी उपज की अपनी विशिष्टता है, लेकिन बाजार तक सीमित पहुंच के कारण किसानों को इसका अपेक्षित मूल्य नहीं मिल पाता था। अब जिला प्रशासन की पहल पर किसानों के धान का संग्रहण, प्रसंस्करण,ग्रेडिंग और आकर्षक पैकेजिंग कर उसे 'कोंडानार प्रीमियम राइस' के नाम से बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे स्थानीय धान को अलग पहचान मिलने के साथ किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के अवसर बढ़ेंगे। बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और मूल्य संवर्धन का लाभ भी किसानों तक पहुंच सकेगा। 'कोंडानार प्रीमियम राइस' की विशेषता यह भी है कि इसके माध्यम से किसानों के साथ ग्रामीण महिलाओं को भी आर्थिक प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के अंतर्गत उड़ान प्रोड्यूसर महिला कृषक कंपनी को धान के संग्रहण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता प्रबंधन,पैकेजिंग और विपणन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहान से जुड़ी स्वसहायता समूह की महिलाएं इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएंगी।

धनोरा में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, 56 गांवों के ग्रामीणों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री साय ने धनोरा में 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। इस स्वास्थ्य केंद्र से धनोरा सहित आसपास के 56 गांवों के लगभग 56 हजार ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अब क्षेत्र के लोगों को सामान्य बीमारियों के उपचार, स्वास्थ्य जांच और अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के लिए दूर-दराज के अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अब तक इस दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीणों को उपचार के लिए जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था, जिससे उन्हें समय और धन दोनों की परेशानी उठानी पड़ती थी। नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन से स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा और हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

आदिवासी समाज ने पारंपरिक रीति-रिवाजों से किया आत्मीय स्वागत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के धनोरा पहुंचने पर आदिवासी समाज के लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। समाज के प्रतिनिधियों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार मुख्यमंत्री के सिर पर साफा बांधकर उनका सम्मान किया। इस दौरान आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, आत्मीयता और अतिथि सत्कार की सुंदर झलक देखने को मिली। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, बस्तर सांसद महेश कश्यप, कांकेर सांसद भोजराज नाग,बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक सु लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, बस्तर आईजी बी.एन. मीणा, कलेक्टर मती नूपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।

बीजेपी का 'बाप तो बाप होता है' गाना...देवेंद्र को रॉकस्टार बनाया,भूपेश पर निशाना,कहा...खुद ऐश किया,बेटे को जेल भिजवाकर मूर्ख बनाया



रायपुर,23 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को रॉकस्टार बनाकर 'बाप तो बाप होता है' गाना तैयार किया गया है। गाने के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल पर निशाना साधा है। गाने के बोल हैं...'बाप ने बेटे को मूर्ख बनाया,खुद ऐश किया,बेटे को जेल भिजवाया।' इसमें कथित शराब सिंडिकेट और 250 करोड़ रुपए का भी जिक्र किया गया है। गाने में आगे कहा गया है कि,'लेकिन बाप तो बाप होता है' और 'बाप बना घोटालों का सरदार, बेटे का था इसमें पूरा किरदार।' इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने और ईडी-आईटी को अपने इशारों पर चलाने का आरोप लगाया।

राष्ट्रीय सचिव की नियुक्ति नहीं मिलने के बाद सियासी चर्चा

दरअसल, AICC की नई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी नहीं मिली। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व ह्रस्ष्ठ मनीष बंछोर की सोशल मीडिया पोस्ट 'बाप तो बाप होता है' चर्चा में आई थी। अब भाजपा ने इसी राजनीतिक संदर्भ को लेकर गाने के जरिए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है।

शराब घोटाले को लेकर भी तंज

भाजपा ने वीडियो में शराब घोटाले और चैतन्य बघेल से जुड़े आरोपों को गाने के बोल में शामिल किया है। चैतन्य बघेल शराब घोटाले से जुड़े मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। वीडियो में लगाए गए राजनीतिक आरोपों को भाजपा के तंज के रूप में देखा जाना चाहिए।

धान खरीदी पर भूपेश बघेल ने कहा... पटवारी हड़ताल सरकार की सोची-समझी साजिश थी,किसानों का पूरा धान खरीदना होगा



धमतरी,23 नवम्बर 2026। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी में आयोजित मितानिन सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए बघेल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पटवारी हड़ताल को समाप्त न होने देना सरकार की सोची समझी साजिश थी, ताकि किसानों की धान खरीदी प्रभावित हो सके और सरकार को सारा धान खरीदना न पड़े। उन्होंने कहा कि लाखों किसानों का रकबा कम कर दिया गया है। तीन-तीन बार चक्रवाती तूफान आने से बेमौसम बारिश हुई,जिससे फसलों को नुकसान हुआ। अभी भी कई किसान चिंता में हैं कि क्या उन्हें फसल क्षति का मुआवजा मिल पाएगा। बघेल ने कहा कि यदि सरकार किसान हित में काम कर रही है तो उसे किसानों का सारा धान खरीदना चाहिए। सरकार भीगे हुए धान को भी खरीदे, नमी ज्यादा बताकर इंकार न करे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि मितानिनों ने कोरोना काल में प्रदेश की स्थिति संभाली। जब भी गर्भवती महिला को जरूरत होती है वो आधी रात को भी तैयार रहती हैं। ऐसे में फर्ज बनता है कि हम उनका सम्मान करें।

मानव तस्करी और घरेलू हिंसा पर सीएम साय ने जताई चिंता,बोले...इसे रोकने के लिए जनआंदोलन जरूरी

रायपुर,23 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यशाला में महिला सुरक्षा, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा और महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित विशेषज्ञ और संबंधित पक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि मानव तस्करी और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं को कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता। भारत में प्राचीन काल से ही नारियों की पूजा की जाती रही है, लेकिन आज भी इन गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें इन समस्याओं को स्वीकार कर इनके समाधान के लिए प्रयास करना होगा।

पेटी और दीवान में छिपाकर रखा 70 लाख का गांजा

ओडिशा से लाकर छत्तीसगढ़ में खपाते थे, किसान से तस्कर बने सगे भाई, 2 सगे भाई समेत 4 गिरफ्तार

बालोद,23 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ओडिशा से गांजा लाकर सप्लाई करने वाले दो सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 139 किलो गांजा जब्त किया गया है। इसकी कीमत 69 लाख 27 हजार 550 रुपए बताई गई है। गांजा 134 पैकेट में रखा था। इसमें से आधा गांजा गुंडरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम खप्परवाड़ा के सगे भाइयों ओमप्रकाश पटेल (28) और कुलेश्वर पटेल (24) के घर से मिला है। दोनों भाइयों ने गांजा लोहे की पेटियों और दीवान में छिपाकर रखा था। पुलिस ने गांजा तस्करी में इस्तेमाल पिकअप, बाइक, मोबाइल और नकदी समेत कुल 85 लाख 72 हजार 550 रुपए की संपत्ति जब्त की है।



मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की थी पहली कार्रवाई

दरअसल, 21 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम अरकार के भीषम सतनामी (28) अपने घर में गांजा रखकर बेच रहा है। इस पर सनौद पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने उसके घर दबिश दी। तलाशी में दो पैकेट और पुड़िया में रखा 1.995 किलो गांजा मिला। पूछताछ में भीषम ने बताया कि उसने यह गांजा गांव के ही कामता प्रसाद कोसरे (43) से खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने कामता से पूछताछ की। उसके पास गांजा सप्लाई करने वाले दोनों भाइयों के मोबाइल नंबर थे।

पुलिस ने कामता से फोन करवाकर दोनों भाइयों को गांजा लेकर रास्ते में मिलने बुलाया। बाइक से गांजा लेकर पहुंचे ओमप्रकाश और कुलेश्वर को पुलिस ने पकड़ लिया।

घर की तलाशी में पेटियों और दीवान से मिले 134 पैकेट

एसपी किरण गंगाराम चव्हाण ने बताया कि दोनों भाइयों को पकड़ने के बाद पुलिस उनके घर पहुंची। तलाशी के दौरान लोहे की पेटियों और दीवान के अंदर गांजे के पैकेट छिपाकर रखे मिले। यहां से कुल 134 पैकेट में 136.56 किलो गांजा जब्त किया गया। पूछताछ में दोनों भाइयों ने बताया कि वे ओडिशा के बालीगुडा इलाके से पिकअप में गांजा लाते थे और बालोद जिले में इसकी सप्लाई करते थे। दोनों करीब एक साल से इस काम में लगे थे।

किस्त चुकाने में परेशानी हुई तो करने लगे तस्करी

पुलिस के मुताबिक, दोनों भाई 2023 में खेती का काम छोड़कर महिंद्रा पिकअप खरीदकर किराये पर चलाने लगे थे। इसके लिए वे कोलकाता और बनारस जाते थे। बाद में पिकअप की किस्त चुकाने में परेशानी होने लगी तो उन्होंने गाड़ी भिलाई फल मंडी में किराये पर लगा दी। इसके बाद दोनों फल-सब्जी लाने के लिए ओड़िशा जाने लगे। इसी दौरान ज्यादा कमाई के लालच में गांजा तस्करी शुरू कर दी। दोनों एक बार में 10 से 20 किलो गांजा लाते थे। इसे घर में छिपाकर रखते और फिर स्थानीय स्तर पर सप्लाई करते थे।

महादेव सट्टा : सौरभ से 15 करोड़ लेने वाला वकील गिरफ्तार

जज-अधिकारियों को सेट करूंगा कहकर लिए थे पैसे,रायपुर में ईडी करेगी पूछताछ

रायपुर,23 नवम्बर 2026। महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में ईडी ने दिल्ली के वकील हिमांशु शेखर उर्फ मोहित को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से उसने जज और अधिकारियों को सेट करने का भरोसा देकर 15 करोड़ रुपए लिए थे। रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सोमवार रात ही उसे पेश किया गया। बताया जा रहा है रात में ही सुनवाई चलेगी। जानकारी के मुताबिक, ईडी की पूछताछ में सौरभ चंद्राकर ने खुलासा किया है कि अपना केस रफा-दफा कराने के लिए उसने हिमांशु को 15 करोड़ रुपए दिए थे। इसी कड़ी में ईडी हिमांशु से पूछताछ करना चाहती है। ईडी के मुताबिक हिमांशु पिछले तीन साल में कई बार दुबई गया और वहां सौरभ चंद्राकर से उसकी मुलाकात हुई थी। एजेंसी इन मुलाकातों और कथित लेन-देन की जांच करना चाहती है।

सौरभ से पूछताछ में सामने आया हिमांशु का नाम : ईडी ने महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को 13 नवंबर को कस्टोडियल रिमांड पर लेकर 19 नवंबर तक पूछताछ की इस दौरान हिमांशु शेखर का नाम सामने आया। इस दौरान सौरभ ने बताया कि उसने अपना मामला रफा-दफा कराने के लिए हिमांशु को 15 करोड़ की रकम दी थी। जांच



एजेंसी को यह भी जानकारी मिली है कि हिमांशु पिछले तीन साल में कई बार दुबई गया था और वहां सौरभ चंद्राकर से उसकी मुलाकात हुई थी।

दुबई जाने से पहले मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया : हिमांशु शेखर को 20 नवंबर को दोपहर करीब 3:03 बजे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोका गया था। वह दुबई जाने वाला था। ईडी रायपुर की ओर से उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे रोकने के बाद ईडी रायपुर जोनल आफिस को को सूचना दी। इसके बाद ईडी अधिकारियों ने जरूरी प्रक्रिया पूरी कर 21 नवंबर की रात 1:10 बजे उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। एजेंसी उसे मुंबई की विशेष PMLA कोर्ट में लेकर पहुंची और दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी,ताकि उसे रायपुर लाकर पूछताछ की जा सके।

समय-सीमा पूरी होने के कारण नहीं मिली रिमांड

ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्विस ने दलील दी कि गिरफ्तारी का समय 20 नवंबर दोपहर 3:03 बजे से नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उस समय हिमांशु किसी जांच अधिकारी की हिरासत में नहीं था। ईडी के मुताबिक, उसकी हिरासत 21 नवंबर की रात 1:10 बजे से मानी जानी चाहिए। कोर्ट में दोपहर 2:45 बजे पेश किए जाने के दौरान एयरपोर्ट से ईडी कार्यालय और फिर कोर्ट तक पहुंचने में लगे करीब डेढ़ घंटे को भी समय-सीमा से बाहर रखने की दलील दी गई। बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए गिरफ्तारी की प्रक्रिया में अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। विशेष अदालत ने ईडी की दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि लुक आउट सर्कुलर रायपुर ईडी ने जारी किया था और उसी के आधार पर हिमांशु को 20 नवंबर को दोपहर 3:03 बजे रोका गया।

क्रिप्टो करेंसी के नाम पर कारोबारी से 1.54करोड़ की ठगी

30प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराई रकम



रायपुर,23 नवम्बर 2026। रायपुर में क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 1 करोड़ 54 लाख 90 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने प्रार्थी को निवेश की रकम पर 25 से 30 प्रतिशत तक मुनाफा देने का भरोसा दिलाया था। इसके बाद उससे अलग-अलग बैंक खातों में रुपए जमा कराए गए। मामले में आजाद चौक पुलिस ने पत्थलगांव निवासी 25 वर्षीय ललित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने प्रार्थी को क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी ट्रेडिंग के कारोबार में निवेश करने पर अच्छा मुनाफा मिलने का लालच दिया था। भरोसे में आकर प्रार्थी ने अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 54 लाख 90 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में धोखाधड़ी का पता चलने पर थाना आजाद चौक में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 191/26 के तहत बीएनएस की धारा 318(4) और 3(5) में केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक खातों में हुए लेनदेन की बारीकी से पड़ताल की।

पूछताछ में आरोपी ललित अग्रवाल ने मामले में धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश किया।

साव बोले...कांग्रेस ने अंबेडकर का कद घटाने की कोशिश की,कहा... अपने दो प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न लेकिन बाबा साहेब को नहीं दिया

रायपुर,23 नवम्बर 2026। कांग्रेस के दो प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया, लेकिन संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को उनके हकदार होने के बावजूद यह सम्मान नहीं दिया गया। यह आरोप डिप्टी सीएम अरुण साव ने लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का कद छोटा करने की कोशिश की, ताकि वे नेहरू-गांधी परिवार के बराबर खड़े न हो सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दो बार लोकसभा चुनाव में बाबा साहेब को हराने की साजिश रची। साव ने कहा कि जो पार्टी संविधान निर्माता का सम्मान नहीं कर पाई, वह किस मुंह से संविधान का सम्मान करने का दावा करती है? उन्होंने ये बातें 26 नवंबर को रायपुर में होने वाले संविधान गौरव दिवस के आयोजन को लेकर



आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं। डिप्टी सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बाबा साहेब को जितना सम्मान दिया है, उतना पहले की किसी भी सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज संविधान और उसके सम्मान की बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन उसे यह भी बताना चाहिए कि उसने संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर के साथ कैसा व्यवहार किया था। साव ने कहा कि बाबा साहेब को भारत रत्न देने का काम भाजपा समर्थित सरकार के समय हुआ। कांग्रेस के दो प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया, लेकिन बाबा साहेब को उनके जीवनकाल में यह सम्मान नहीं मिला,जबकि वे इसके हकदार थे। अरुण साव ने केंद्र सरकार की ओर से बाबा साहेब के सम्मान में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बाबा साहेब की जन्मभूमि पहुंचे और उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। उनके जीवन और योगदान को याद करते हुए सरकार ने बाबा साहेब से जुड़े पंचतीर्थों का विकास कराया। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब की जन्मभूमि पर स्मारक बनाया गया। लंदन में उनकी शिक्षा से जुड़ी जगह पर डॉ. अंबेडकर मेमोरियल बनाया गया। नागपुर की दीक्षाभूमि का कायाकल्प किया गया। मुंबई की चैत्यभूमि में स्मारक और समाधि स्थल का निर्माण कराया गया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)